जून, 2021 वर्ष: 42 अंक: 6



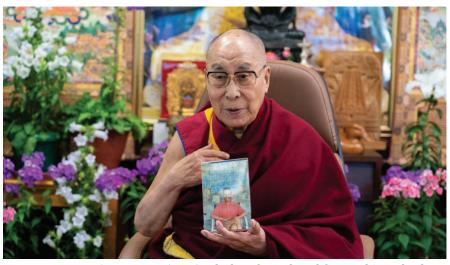


जून, 2021 वर्ष: 42 अंक: 6

देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित

तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में



परम पवन दलाई लामा जी स्वर्गीय फ्रांसिस्को वरेला की याद मे आयोजिद एक वेबिनार मे जुड़े।

समाचार -

समाचार -परम पावन दलाई लामा एक बेहतर दुनिया के लिए संवाद- फ्रांसिस्को वरेला की याद सिचुआन में तिब्बती निजी भाषा स्कूल बंद स्कूल बंद होने से तिब्बती इलाकों में भाषा अधिकार पर चीन के प्रतिबंध और सख्त तिब्बती विद्वान को उनके लेखन के लिए गिरफ्तार किया गया, दो साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रहे लापता तिब्बती भिक्षु को सजा सुनाई गई, जेल भेजा गया - परिवार चीन ने निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क करने के आरोप में तिब्बतियों को ड्रिरू में गिरफ्तार किया अखिल भारतीय तिब्बत समर्थको के कोर ग्रुप – भारत ने सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के साथ अपनी पहली आभासी बैठक आर्यभूमि और पृथ्वी के तीसरे ध्रुव का संरक्षण: विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार भारत-तिब्बत सीमा पर गलवान घाटी में भारतीय सेना के शहीदों का सम्मान भारत तिब्बत समन्वय संघ ने विश्व शरणार्थी 10 दिवस पर तिब्बती पुनर्जागरण का जश्न मनाया

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में दलाई लामा स्ट्रीट का उद्घाटन
डेनमार्क में चीन के राजदूत, फेंग टाई को सेंट्रल कोपेनहेगन में एक बैठक स्थल के बाहर विरोध का 13 सामना करना पड़ा
कनाडा ने 43 देशों के साथ तिब्बत पर गंभीर चिंता जताई; झिंझियांग जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अनुमति देने को 14 चीन से आह्वान किया
सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ: अत्याचारों की पराकाष्ठा 15
इतिहास गवाह है कि हिमालय में एशिया को नियंत्रित करने की कुंजी है; भारत को चीन से सावधान रहना 16 चाहिए

कनाडा के 'पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' ने

सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग के साथ तिब्बत दिवस मनाया

विचार डॉ. त्सेवांग दोरजी धर्मशाला में तिब्बत नीति संस्थान में रिसर्च फेलो हैं।

प्रधान संपादक जमयंग दोरजी , जिगमे सुलट्टिम

सलाहकार संपादक

प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक तेनजिन पलजोर , तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक जामयंग छोपेल, छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय:

भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र एच -१० लाजपत नगर -३ नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें।

> मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत -तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट www.indiatibet.com Email: indiatibet7@gmail.

नवनिर्वाचित सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग की प्राथमिकतायें

लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित तिब्बत के सिक्योंग अर्थात राजप्रमुख पेंपा त्सेरिंग के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बत सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है। पहली प्राथमिकता है तिब्बत समस्या का समाधान। परमपावन दलाई लामा एवं निर्वासित तिब्बत सरकार के मतानुसार तिब्बत समस्या का व्यावहारिक एवं स्थायी हल है तिब्बत को वास्तविक स्वायता। चीन के संविधान तथा उसके राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अंतर्गत चीन की एकता-अखंडता एवं संप्रभुता की सुरक्षा करते हुए तिब्बतियों को स्वशासन का अधिकार मिल जायेगा। चीन सरकार वैदेशिक मामले तथा प्रतिरक्षा विभाग स्वयं संभालेगी एवं शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और उद्योग आदि अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तिब्बतियों के पास होगा। इसी को "मध्यममार्ग" कहा जाता है। इसी से "वास्तविक स्वायता" की मांग भी जुड़ी है। विस्तारवादी चीन सरकार ने स्वतंत्र तिब्बत देश पर 1959 में अवैध नियंत्रण स्थापित करके उसके भूगोल को विकृत कर दिया है। तिब्बत के कई क्षेत्र चीन ने अपने भुभाग में मिला लिये हैं। इसके अन्य क्षेत्रों को अपने साम्राज्यवादी हित में प्रशासनिक फेरबदल के सहारे काट-छाँट दिया है। तिब्बती समुदाय चाहता है कि चीन सरकार तिब्बत के मूल भौगोलिक क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करते हुए समूचे क्षेत्र को स्वायता प्रदान करे। विश्व समुदाय को गुमराह करने के लिये चीन ने तिब्बत को जो स्वायत्तता दे रखी है वह पूर्णतः अस्वीकार्य है।

विश्वभर में तिब्बत समर्थक संगठन एवं देश तिब्बत की चीन से पूर्ण आजादी के पक्ष में हैं। लेकिन वे भी मध्यम मार्ग नीति का समर्थन कर रहे हैं। तिब्बती समुदाय चीन सरकार द्वारा तिब्बत के चीनीकरण से चिंतित है। षड्यंत्रपूर्वक तिब्बती पहचान मिटाई जा रही है। वहाँ के धार्मिक-सांस्कृतिक केन्द्र, तिब्बती भाषा,इतिहास तथा जीवनमूल्यों को नष्ट किया जा रहा है। "दुनिया की छत" एवं "तीसरा धुरव" चीन की भोगवादी नीति के कारण सिकुड़ते-पिघलते ग्लेशियर का क्षेत्र बनने की ओर है। तिब्बत के ग्लेशियर नष्ट होने से कई देशों में जल संकट पैदा हो जायेगा। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में तिब्बती पहचान को सुरक्षित रखने के लिये तिब्बती समुदाय पूर्ण आजादी की मांग को छोड़कर सिर्फ "वास्तविक स्वायत्तता" लेने को तैयार है।

सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग की कोशिश चीन के साथ परमपावन दलाई लामा एवं निर्वासित तिब्बत सरकार की बंद पड़ी वार्ता पुनः प्रांरभ करने की है। इसे पुनः प्रारंभ करने के पक्ष में सारे तिब्बत समर्थक हैं। शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तिब्बती संघर्ष की उपेक्षा इसे हिसंक बना सकती है। इसलिये भी वार्ता पुनः प्रारंभ होनी चाहिये।

पेंपा त्सेरिंग की प्राथमिकता भारतीय सहयोग को और अधिक रचनात्मक बनाने की है। परमपावन दलाई लामा ने हजारों तिब्बतियों के साथ भारत को ही शरण लेने के लिये चुना था। वे इसे अपना दूसरा घर कहते हैं। वे इसे गुरु तथा तिब्बत को भारत का चेला कहते हैं। तिब्बत को चीनी अतिक्रमण से तत्कालीन भारत सरकार बचा नहीं सकी। "पंचशील" और "हिन्दी चीनी भाई भाई" के नारों के बीच "सफेद कबूतर" उड़ायें जा रहे थे। इस ऐतिहासिक भूल के बावजूद तत्कालीन तथा बाद में भी भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा तिब्बती समुदाय की भरपूर सहायता जारी है। अनेक महत्वपूर्ण तिब्बती शिक्षण

संस्थान, व्यवस्थित तिब्बती सेटलमेंट्स, बौद्ध मठ, चिकित्सालय, रोजगार केन्द्र एवं बिजली-पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता इसके प्रमाण हैं। इस भारतीय सहयोग और समर्थन के लिये पेंपा त्सेरिंग द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन स्वाभाविक है। उनका प्रयास है कि तिब्बती समुदाय भारत के प्रति सदैव सदुव्यवहार का परिचय देता रहे।

नई तिब्बत सरकार की प्राथमिकता में कोविड टीकाकरण भी शामिल है। साम्यवादी चीन के वुहान से फैली कोरोना महामारी ने तिब्बती समुदाय को भी संकटग्रस्त कर दिया है। तिब्बत सरकार का सुव्यवस्थित प्रयास है कि भारत एवं नेपाल में रह रहे तिब्बतियों का टीकाकरण किया जाये, क्योंकि महामारी से बचाव के लिये ऐसा करना जरुरी है। कोरोना से सक्रंमित तिब्बतियों को ऑक्सीमीटर समेत कई आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा उन्हें अन्य स्वास्थ्य सुविधायें दी जा रही हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आने से कई तिब्बती उपने परिजन और रोजगार खो चुके हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिये प्रयासरत कोविड-19 टास्कफोर्स का पुनर्गठन किया गया है। इस कदम से कोरोना महामारी से पीड़ित तिब्बतियों को भरपूर मदद मिलेगी तथा इस महामारी के विस्तार को रोका जा सकेगा।

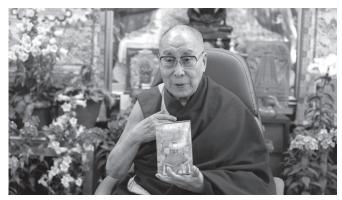
मई 2021 में नवनिर्वाचित तिब्बत सरकार एवं इसके प्रमुख पेंपा त्सेरिंग को शुभकामनाओं का क्रम जून में भी जारी रहना सुखद है। ऐसे समय में भारत को भी तिब्बती मामले में व्यावहारिक एवं ठोस कदम उठाने होंगे। भारत की सीमा पर चीन सरकार रेलवे लाइन बिछा चुकी। अब सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है ताकि वह कम समय और संसाधन में भारत की सीमा पर सैनिक सिक्रयता बढ़ा सके। उसने तिब्बतियों को चीनभक्त सैनिक बनाना शुरू कर दिया है। भारत में रह रहे तिब्बतियों ने भारतीय सैनिक के रूप में चीनी सेना एवं उसकी सामरिक रणनीति को काफी नुकसान पहुँचाया था। गलवान घाटी के इसी शर्मनाक अनुभव ने चीन को प्रेरित किया है कि वह तिब्बतियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सैनिकों के रूप में करे। चीन की हर चाल का जवाब देने के लिये भारत को तैयार रहना है।



प्रो0 श्यामनाथ मिश्र पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान) मी.-9829806065, 8764060406 E-mail & facebook:- shyamnathji@gmail.com

• परम पावन दलाई लामा एक बेहतर दुनिया के लिए संवाद- फ्रांसिस्को वरेला की याद dalailama.com

09 जून, 2021



परम पवन दलाई लामा जी स्वर्गीय फ्रांसिस्को वरेला की याद मे आयोजिद एक वेबिनार मे जुड़े।

थेकचेन छलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। 09 जून की सुबह जब परम पावन दलाई लामा ने अपने आवास के उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ से वे ऑनलाइन आभासी बैठकों में भाग लेते हैं, तो वे आभासी बैठक में भाग लेनेवाले सभी लोगों को दिखाने के लिए अपने साथ फ्रांसिस्को वरेला की तस्वीर लेकर आए और सामने रख दिया। इस फोटो को वे अपने आवास में रखते हैं। माइंड एंड लाइफ यूरोप के प्रबंध निदेशक गैबोर करसाई ने आज के कार्यक्रम 'एक बेहतर दुनिया के लिए संवाद – फ्रांसिस्को वरेला की याद' में उनका स्वागत किया। यह कार्यक्रम 'फ्रांसिस्को एंड फ्रेंड्स -एन एम्बोडिमेंट ऑफ रिलेशनशिप; नामक शृंखला की पहली कड़ी थी। कार्यक्रम की यह शृंखला 'माइंड एंड लाइफ' के प्रमुख संस्थापकों में से एक वरेला की याद में बनाई गई है, जिनका बीस साल पहले निधन हो गया था। करसाई ने सभी लोगों को वरेला की माइंड एंड लाइफ की शुरुआती मीटिंग्स की कई तस्वीरें देखने के लिए आमंत्रित किया। ईटीएच, ज्यूरिख में बायोकैमिस्ट्री के प्रोफेसर एमेरिटस डॉ. पियर लुइगी लुइसी ने बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने 1983 में ऑस्ट्रिया के एल्पबैक में आयोजित एक कार्यक्रम का स्मरण किया, जब परम पावन और फ्रांसिस्को वरेला पहली बार मिले थे। यह एक ऐसा अवसर था जो प्यार और दोस्ती के माहौल में बीता। लुसी ने पूछा कि किस बात ने वरेला के साथ मित्रता को परम पावन के लिए विशेष बना दिया। परम पावन ने उत्तर दिया, 'जब मैं बहुत छोटा था, मेरी रुचि यांत्रिक चीज़ों में थी। मेरे पास एक मूवी प्रोजेक्टर था जो 13वें दलाई लामा का था और इस बारे में मेरी जिज्ञासा कि कैसे छोटी बैटरी ने ड्राइव करने और प्रोजेक्टर को रोशन करने की शक्ति पैदा की, जिसने मुझ्मे बिजली में रुचि को जगाया। साथ ही मैं बचपन से ही बौद्ध दर्शन के अध्ययन में लगा हुआ था।"जब मैं वरेला से मिला, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो एक वैज्ञानिक था, लेकिन जिसकी बौद्ध धर्म में भी गहरी दिलचस्पी थी। जब वे बौद्ध दृष्टिकोण से बोलते थे तो वे कहते थे, 'मैं यह अपनी बौद्ध टोपी पहने हुए कह रहा हूं' और बाद में जब वे वैज्ञानिक राय दे रहे होते तो कहते, 'अब मैं अपने वैज्ञानिक की टोपी पहन रहा हूं।' मैंने महसूस किया कि मुझे उनके जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो बौद्ध धर्म को समझता हो लेकिन पेशेवर रूप से वैज्ञानिक भी हो। उन्होंने मुझे प्रभावित किया और मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं आज भी उसकी तस्वीर अपने कमरे में रखता हूं।

परम पावन ने आगे कहा, 'बाद में मुझे कई और वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर

प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि विज्ञान हाल ही में पश्चिम में विकसित हुआ है जहां ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और कुछ हद तक इस्लाम का पालन किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों या धार्मिक लोगों के बीच मन और भावनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। और फिर भी मन परिष्कृत है। यह हमें सोचने, ध्यान करने और बदलने में सक्षम बनाता है।' अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए, हमें मन और भावनाओं की प्रणाली के काम करने के तरीके की बेहतर समझने की आवश्यकता है। फ्रांसिस्को वरेला ने उदाहरण के द्वारा दिखाया कि विज्ञान और बौद्ध धर्म साथ-साथ काम कर सकते हैं।

परम पावन ने कहा, 'उनका और मेरा मानना रहा है कि हम एक जीवन के बाद दूसरा जीवन जीते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वरेला को अपना अगला जीवन मेरे करीबी दोस्तों के बीच मिलेगा। हम एक-दूसरे को पहचानें या नहीं, हम एक-दूसरे के लिए उसके पिछले जीवन के अनुभव के पिरणामस्वरूप मजबूत भावनाएं रखेंगे। जब मैं बहुत छोटा था तो कुछ लोग मेरे घर आए। ये सब लोग 13वें दलाई लामा के करीबी थे और मैंने पहचान लिया कि वे कौन हैं।' उन्होंने कहा, 'वरेला और मैंने एक मजबूत संबंध विकसित किया और मुझे यकीन है कि अगर मैं 10-20 साल और जीवित रह गया, तो मैं एक ऐसे बच्चे से मिलूंगा, जिसके पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ खास बात होगी। अब मैं अपने पुराने दोस्त के बारे में बात करके खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि उसकी पत्नी भी हमारे साथ है।'

उन्होंने कहा; एक बेहतर दुनिया के लिए संवाद; बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आज की दुनिया में अपने व्यापक भौतिक विकास के साथ, जिसमें हथियारों का निर्माण भी शामिल है, मेरे राष्ट्र मेरे लोगों पर बहुत अधिक दबाव है। नेताओं का केवल एक संकीर्ण फोकस होता है। जब लोगों का एक और समूह एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, तो हम भी उन्हें आसानी से शत्रुतापूर्ण मानते हैं और उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं। हालांकि, कुल मिलाकर वैज्ञानिक इस या उस समूह के बजाय पूरी मानवता से अधिक चिंतित हैं। परम पावन ने कहा, आज, 'हम' और 'उन' की भावना बहुत मजबूत है। 'मेरा दोस्त' या 'मेरा दुश्मन' की बहुत अधिक समझ है। लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। मैं मानवता की एकता के विचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। मनुष्य के रूप में हम सब एक जैसे हैं। इससे बढ़कर बात यह है कि हम सभी को इस ग्रह पर एक साथ रहना है। हमारे पास एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है। हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए, हमें अब जीवित सभी सात अरब मनुष्यों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए।

परम पावन ने याद दिलाया, 'हमारा अतीत बहुत अधिक हिंसा से रक्तरंजित रहा है। लेकिन देखिए यूरोपीय संघ (ईयू) ने क्या हासिल किया है। लंबे समय से दुश्मन फ्रांस और जर्मनी अपनी ऐतिहासिक शत्रुता को भूलकर यूरोपीय संघ का निर्माण करने में आगे आ गए। तब से, सदस्य राज्यों के बीच कोई लड़ाई या हत्या नहीं हुई है। पूरी दुनिया इस तरह के दृष्टिकोण को क्यों नहीं अपना सकती? केवल मेरे देश के बारे में सोचने के बजाय, पूरी दुनिया को अपने संदर्भ में सोचें। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।'

'हालांकि, मैं' भारत में रहने वाला सिर्फ एक शरणार्थी हूं, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे लंबे संबंध हैं। भारत हमारा पड़ोसी है, लेकिन यह हमारे सभी ज्ञान का स्रोत भी है। यह हमारे प्राचीन घर जैसा है।'

उन्होंने कहा, 'मानवता की एकता के लिए काम करने से मुझे सहज महसूस होता है क्योंकि इससे मुझे यह महसूस करने में मदद मिलती है कि मैं जहां भी जाता हूं, जिससे मैं मिलता हूं, वह मेरे जैसा दूसरा इंसान है। मनुष्य के रूप में हम सब भाई-बहन हैं। इस ग्रह पर सभी मनुष्यों की एकता के बारे में सोचने से मन को शांति मिलती है क्योंकि तब डर या अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं रह जाता है।

परम पावन ने कहा, 'मैं मानवता की एकता और सभी धार्मिक परंपराओं के मूल्य की मान्यता के इस विचार को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि सभी करुणा के महत्व को सिखाते हैं। मैं पारिस्थितिकी के लिए भी प्रतिबद्ध हूं। तिब्बत में पुरानी पीढ़ियों ने मुझे बताया कि आज की तुलना में पहले बहुत अधिक बर्फ हुआ करती थी। यह महत्वपूर्ण है

क्योंकि तिब्बत उन प्रमुख निदयों का स्रोत है जो एशिया के बड़े हिस्से में जल की आपूर्ति करती हैं। इसलिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।' माइंड एंड लाइफ यूरोप के अध्यक्ष एमी कोहेन वरेला ने परम पावन से पूछा कि उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ संवाद में शामिल होने के लिए इतना समय क्यों दिया। उन्होंने तिब्बती में उत्तर दिया, जिसका थुप्टेन जिन्पा द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, कि एक बौद्ध के रूप में वह प्रतिदिन स्वयं से पूछते हैं कि वे सभी सत्वों की सहायता के लिए क्या कर सकते हैं। वह शांतिदेव के 'बोधिसत्व के मार्ग में परिवेश' के एक प्रमुख श्लोक पर चिंतन करते हैं-

जब तक अंतरिक्ष कायम है, और जब तक सत्वगुण रहते हैं, तब तक मैं भी रहूं दुनिया के दुखों को दूर करने में मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि वे नागार्जुन की ;प्रेसिएस गारलैंड (अनमोल / बहुमूल्य); से एक श्लोक पर भी विचार करते हैं: क्या मैं हमेशा आनंद की वस्तु बन सकता हूं सभी जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार और बिना किसी हस्तक्षेप के, जैसे पृथ्वी हैं, पानी, आग, हवा, जड़ी-बूटियाँ और जंगली जंगल।

उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया की जो भी मदद कर सकता हूं, मैं अपना जीवन उसी के लिए समर्पित करता हूं।' परम पावन ने आगे कहा, 'मैं अपने दैनिक क्रियाकलापों में आचार्य नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित जाग्रत मन की व्यापक साधना के साथ-साथ शून्यवाद के गहन दृष्टिकोण को विकसित करने पर जोर देता हूं। जहां तक जाग्रत मन का संबंध है, मैंने एक साधना पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे स्वयं और पर के बीच समानता और आदान-प्रदान कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोत्साहन के रूप में शांतिदेव ने किया था। जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने स्वयं के सुख का त्याग नहीं करता, उसके लिए बुद्धत्व की प्राप्ति निश्चित रूप से असंभव है। जन्म- मरण के चक्र के अस्तित्व में रहते सुख हो भी कैसे सकता है?

संसार में जो भी प्राणी कष्ट में पड़े हुए हैं वे सब अपने सुख की इच्छा के कारण हैं। दूसरी ओर संसार में जितने भी प्राणी सुखी हैं, वे दूसरों के सुख की इच्छा के कारण ऐसी स्थिति में हैं।

हम जो समस्याओं का सामना करते हैं, वे हमारे 'मैं' और 'मुझे', 'हम' और 'उन' के विचार में निहित हैं। आइए सभी जीवों के कल्याण की भावना को एक तरफ रख दें और कम से कम सभी मनुष्यों के कल्याण की भावना से काम करें और इसी बारे में सोचें। इस तरह की आत्मीयता के आधार पर हम अपने सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में सक्षम होंगे ताकि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बच सकें।'

हुनेल विश्वविद्यालय, लंदन मनोविज्ञान में विरिष्ठ व्याख्याता एलेना एंटोनोवा ने परम पावन से पूछा कि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत का उनकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने दोहराया कि उनकी बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी। एक बार जब वे भारत पहुंचे तो वे कार्यरत वैज्ञानिकों से मिल पाए और उन्हें पता चला कि मन और भावनाओं के बारे में उनकी समझ अपर्याप्त थी। जहां बौद्ध धर्म 51 मानसिक कारकों और उनमें से उपसमूहों का वर्णन करता है, वहीं अंग्रेजी भाषा में केवल एक शब्द है- भावना।

उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी कुछ भावनाएं हमारे लिए समस्याएं पैदा करती हैं। हमें इनसे निपटने की तकनीक सीखनी होगी। अगर हमें अपनी सबसे अधिक परेशानी वाली भावनाओं से निपटना है तो हमें मारक औषधियों और उन्हें विकसित करने के तरीकों की खोज करनी होगी। जैसे-जैसे हमारी समझ बढ़ेगी हम प्रगति करेंगे।

इस दृष्टि से बौद्ध दृष्टिकोण विज्ञान के समान है।

'विज्ञान हमें मानव शरीर और उस भौतिक दुनिया का ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें हम रहते हैं। लेकिन हम सभी शांति और आनंद पाना चाहते हैं और इसका मतलब है कि हमें अपने मन का ख्याल रखना होगा। भावनाएं समस्या पेश करती हैं, लेकिन समाधान फिर से मन में होता है। हालांकि क्रोध बहुत परेशान करने वाला होता है, लेकिन हम इसे दूर करने की कामना करके ही इससे नहीं निपट सकते। हम इससे तभी निपट सकते हैं जब हम यह जान लें कि यह किस कारण से उत्पन्न होता है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और प्रेम-कृपा के द्वारा कैसे इसका प्रतिकार किया जा सकता है। हमें सबसे पहले अपने खुद का दृष्टिकोण ठीक करने और अपने मन को समझना सीखना होगा। वरेला ने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के संयोजन की आवश्यकता को पहचाना और मैंने समझा, 'यही सच है'।

परम पावन ने कहा, 'मुझे आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देने में इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में शामिल आध्यात्मिक शिक्षाओं के ज्ञान को नियोजित कर सकते हैं। बच्चों को सूचनाओं को याद रखने के लिए उनके दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन भारतीय परंपरा में मन को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, तेज, मर्मज्ञता और विशाल बुद्धि विकसित करना शामिल था जो अधिक व्यापक समझ को सक्षम बनाता है। इसे धर्म से न जोड़ते हुए शिक्षा के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास प्राकृतिक कौशल और क्षमताएं हैं जिन्हें प्रशिक्षण के साथ बढ़ाया जा सकता है। जब महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जाता है तो मैं एक चीज का इंतजार कर रहा हूं कि तब मैं दिल्ली में समय बिताऊंगा और मन के प्राचीन भारतीय ज्ञान का दोहन कर इसमें वर्णित मानसिक प्रशिक्षण के बारे में सीखने की कोशिश करुंगा।'

परम पावन ने लुसी से कहा कि आधुनिक विज्ञान अब भी भौतिकवाद की ओर बहुत अधिक उन्मुख है। यहां तक कि मानव का अनुभव भी चेतना के संबंध के बजाय मस्तिष्क के संदर्भ में ही देखने की रही है। यदि मस्तिष्क ही ध्यान का एकमात्र केंद्र है और चेतना की व्यक्तिपरकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो इसका मतलब है कि यह मानव अनुभव की पूरी तस्वीर नहीं पेश कर पा रहा है। यह चेतना या मन की अनूठी विशेषता को छोड़ देगा जो कि व्यक्तिपरक आयाम में महसूस किया जाता है।

उन्होंने कहा कि हम सभी आनंद महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या हमें अपने अंदर की शांति है। परम पावन ने आशा व्यक्त की कि विज्ञान स्कूली बच्चों को शिक्षा के माध्यम से यह दिखाने और समझाने में सक्षम होगा कि कैसे मन की शांति, दया और करुणा जैसे गुणों को विकसित किया जा सकता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परम पावन ने कहा, 'वैज्ञानिक भी हम लोगों की तरह ही इंसान हैं। वे भावनात्मक समस्याओं का भी सामना करते हैं और मन की शांति चाहते हैं। लेकिन मन की शांति को विकसित करना सीखने के लिए दिमाग के काम करने की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। एक विश्लेषणात्मक और चिंतनशील दृष्टिकोण के बाद इसे लाने में मदद मिल सकती है। वर्षों से, जैसे-जैसे हमारे संवाद चल रहे हैं, अधिक से अधिक वैज्ञानिक अपनी मानसिक बेहतरी पर ध्यान दे रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'उन्होंने विश्लेषण किया है कि कैसे क्रोध उनके मन की शांति को भंग करता है। उन्होंने जांच की है कि उनका यह क्रोध और अशांति कहां से आती है और यह कैसे उत्पन्न होती है। शांतिदेव इसका कारण परिप्रेक्ष्य में अंतर को बताते हैं। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य धारण करता है, उसके समक्ष शत्रुतापूर्ण, चिड़चिड़ा व्यवहार करनेवाला व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बन जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण चीजों को देखने का एक अलग तरीका विकसित करता है जिससे कि वास्तविक परिवर्तन हो सकता है।

उन्होंने कहा कि शून्यवाद से संबंधित इस तरह की जांच के एक अन्य पहलू के तौर पर इस सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए होगा कि यह 'मैं' या; कौन हूं या क्या हूं? इसका क्या मतलब है? क्रोध और मोह का आधार यह है कि इसमें एक वास्तविक; शामिल है। नागार्जुन के;मध्य मार्ग की मौलिक बुद्धि; में एक श्लोक है जो तथागत या बुद्ध की पहचान की जांच करता है। हम इसे अपने संदर्भ में और अपने घटक भागों के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में बदल सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 'इस श्लोक पर विचार करते हुए हम यह पहचान सकते हैं कि; न तो मन-शरीर के घटकों में से एक है, न ही उनसे अलग है। मन-शरीर के घटक; पर (आश्रित) नहीं हैं, न ही उन पर; मैं; (आश्रित) हैं। मैं; में मन-शरीर के घटक नहीं हैं। तो ;मैं; कौन हूँ? हम पाते हैं कि कोई वास्तविक, ठोस आत्मा नहीं हैं जिसे हम इंगित कर सकें।

हमें दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक तरफ तो भावनाओं और उनके प्रतिशोध की जांच करना है।

लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल करना कि क्या एक वास्तविक, ठोस 'मैं' या 'मुझे' वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद है जैसा कि यह प्रतीत होता है। इसका कुछ असर होगा।

परम पावन ने सुझाया, 'कल्पना कीजिए कि आपकी प्रबल भावनाओं को वैसे ही व्यक्त किया जाता है जैसा कि वाद-विवाद में आपके विरोधियों ने बताया है। क्रोध और मोह को चुनौती देकर यह कहें कि यह; स्व; कहाँ है, जिसका वे बचाव करते हैं। अंतत - वे स्वीकार करेंगे कि ऐसा कोई स्व नहीं है। हम वास्तव में कई धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं जो हमारी गलत धारणाओं के पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम प्रतीत्य समुत्पाद के एक कार्य के रूप में मौजूद हैं। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता एक झूठा प्रक्षेपण है जिसका हमारी

भावनाओं पर शक्तिशाली प्रभाव पडता है।'

परम पावन ने चंद्रकीर्ति के;मध्य मार्ग में प्रवेश; के छंदों की ओर संकेत किया जो पारंपिरक और परम सत्य के दो पंखों पर ज्ञानोदय और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारी सामान्य मानवता की भावना को बढ़ावा देने के संबंध में परम पावन ने कहा कि वे इसे व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं। हम इस एक ग्रह को साझा करते हैं और हमारी दुनिया वास्तव में अन्योन्याश्रित है। जब; और; के संदर्भ में बहुत अधिक विभाजन होता है, तो यह पारस्परिक रूप से विनाशकारी होता है। कोई नहीं जीतता। दूसरी ओर, अगर हम मानवता की एकता की भावना को मजबूत करते हैं और उन लोगों को गले लगाते हैं जो हमसे अलग हैं, तो हम सभी अधिक शांति से और अधिक खुशी से एक साथ रहना सीख सकते हैं। उन्होंने कहा, यह जीवित रहने की साधारण बात है।

परम पावन ने टिप्पणी की कि आस्तिक धार्मिक परंपराओं के अनुयायी स्रष्टा के तौर पर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिसे वे ईश्वर के रूप में देखते हैं। और एक ईश्वर की सन्तान होने के नाते वे कहते हैं कि हम सब भाई-बहन हैं। अगर हम आपस में लड़ते और मारते हैं, तो पिता परमेश्वर को कैसा लगेगा? उन्होंने घोषित किया कि यही कारण है कि हमें खुशी-खुशी और सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रहना सीखना होगा। गैबर करसाई ने कहा कि बैठक का समापन इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकता था। उन्होंने परम पावन को उनकी बुद्धिमत्ता और मित्रता के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उन्होंने अध्ययन के एक नए क्षेत्र को जन्म दिया है- चिंतनीय विज्ञान।

सिचुआन में तिब्बती निजी भाषा स्कूल बंद

स्कूल बंद होने से तिब्बती इलाकों में भाषा अधिकार पर चीन के प्रतिबंध और सख्त

rfa.org, 03 जून, 2021

पश्चिमी चीन के सिचुआन में अधिकारी तिब्बती भाषा में पढ़ाने वाले निजी तिब्बती स्कूलों को बंद कर रहे हैं। क्षेत्रीय सूत्रों का कहना है कि वे तिब्बती छात्रों को सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जहां उन्हें चीनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षण सामग्री के उपयोग में एकरूपता को बढ़ावा देने के नाम पर यह कदम उठाया जा रहा है। कद्र्ज़ें (गांज़ी) तिब्बती स्वायत्त प्रांत में सेरशुल (चीनी, शिकू) काउंटी में एक स्रोत ने आरएफए को बताया कि सिचुआन के दज़ाचुखा क्षेत्र में पहले कई निजी स्कूल थे जहां तिब्बती भाषा और संस्कृति सिखाई जाती थी।

आरएफए के सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'लेकिन 2020 के अंत से और बिना किसी वास्तविक कारण के इन सभी स्कूलों को बंद करने को मजबूर किया गया और बच्चों को सरकारी निगरानी वाले स्कूलों में जाना पड़ा।' सूत्र ने कहा कि प्रभावित बच्चों के माता-पिता और अन्य स्थानीय तिब्बतियों ने थोपी गई इन बातों को लेकर बहुत चिंता जताई है और कहा कि युवा तिब्बतियों को उनकी संस्कृति और भाषा से दूर रखने से भविष्य में गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा, 'तिब्बती खानाबदोश परिवार जो अब तक अपने बच्चों को चीनी सरकार की निगरानी वाले स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, उन्हें अब ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।'

भारत के धर्मशाला में स्थित तिब्बती नीति संस्थान में एक शोधकर्ता कर्मा तेनज़िन ने कहा कि सेरशुल में स्कूलों को बंद करके चीन अपने ही कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, जिनमें जातीय अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा सीखने के अधिकार की गारंटी दी गई है।

तेनज़िन ने कहा, 'तिब्बती भाषा और संस्कृति सिखाने वाले स्कूलों को जबरन बंद करने का यह कृत्य तिब्बत की (राष्ट्रीय) पहचान को खत्म करने के चीनी सरकार के प्रयासों की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है।'

टाउनशिप में कठोर नियंत्रण तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ लगातार विरोध



तिब्बत के सिचुआन क्षेत्र में तिब्बती स्कूलों को जबरन बन्द करवाया।

के परिदृश्य को और स्पष्ट करते हुए सेरशुल के ड्ज़ा वोन्पो टाउनशिप के एक निवासी ने आरएफए से कहा कि इस टाउनशिप इलाके में जीवन कठोर नियंत्रण में रहता है। यहां पर निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की तस्वीरों को रखना एक गंभीर अपराध माना जाता है।

उन्होंने कहा, 'तिब्बती निर्वासित समुदाय के साथ संवाद करना भी हाल के दिनों में बहुत मुश्किल हो गया है और अगर चीनी अधिकारी उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं तो उन्हें तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता है।' तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ 1959 में हुए असफल राष्ट्रीय विद्रोह के दौरान तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा को भारत में निर्वासन में भाग आना पड़ा था। इससे पहले चीन ने इस हिमालयी स्वतंत्र देश तिब्बत पर 1950 में ही बलपूर्वक कब्जा कर लिया था। इसके बाद से हमेशा परम पावन दलाई लामा की तस्वीर रखने पर या उनका जन्मदिन सार्वजनिक तौर पर समारोह पूर्वक मनाने पर तिब्बती लोगों को कड़ी सजा दी जाती रही है। चीन की 2010 की जनगणना के अनुसार, चीन में रह रहे कुल 62 लाख तिब्बतियों में से, लगभग 15 लाख तिब्बती ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी सिचुआन प्रांत के तिब्बती हिस्सों में रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में तिब्बती भाषा अधिकार के लिए आंदोलन तिब्बती राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार, मठों और कस्बों में अनौपचारिक रूप से आयोजित भाषा पाठ्यक्रमों को आम तौर पर 'अवैध सभा' माना जाता है और पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए सांगेय कुंचोक द्वारा रिपोर्ट किया गया। तेनज़िन डिकी द्वारा अनूदित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखित।

• तिब्बती विद्वान को उनके लेखन के लिए गिरफ्तार किया गया, दो साल तक बिना किसी मुकदमें के जेल में रहे

चीनी अधिकारी तिब्बती राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लेखकों, गायकों और कलाकारों को अक्सर जेल में डाल दिया जाता है। rfa.org, 08 जून, 2021

दो साल पहले अज्ञात आरोपों में गिरफ्तार एक तिब्बती लेखक पर अभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया है और परिवार के सदस्यों को उनके बारे में अंधेर में रखा जा रहा है। तिब्बती सूत्रों ने यह जानकारी दी है। तिब्बत में रहने वाले एक सूत्र ने आरएफए को बताया कि लोबसांग ल्हुंडुप को जून 2019 में पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू में एक निजी सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र में काम करने के दौरान हिरासत में लिया गया था। व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर आरएफए के सूत्र ने बताया, 'ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने सांस्कृतिक केंद्र के मालिक को उनके द्वारा उपयोग की जा रही शिक्षण सामग्री के बारे में बताया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।' सूत्र ने कहा, 'ल्हुंडुप एक मिलनसार व्यक्ति हैं और कई लोगों को उनके बारे में पता है। उनके दोस्तों ने इस उम्मीद में अब तक उनके बारे में बात करने से परहेज किया है कि वह रिहा हो जाएंगे।' लेकिन उनका मुकदमा अभी भी लंबित है। उनके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही किसी को उनसे



मिलने की अनुमित दी गई है।' सूत्रों ने कहा कि 1980 में जन्मे ल्हुंडुप सिचुआन के गोलोग (चीनी- गुओलुओ) तिब्बती स्वायत्त प्रांत के पेमा जिले के मूल निवासी हैं। वह 11 साल की उम्र में भिक्षु बन गए और सिचुआन के लारुंग गर तिब्बती बौद्ध अकादमी में अध्ययन किया, जहां निवास कर रहे हजारों भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बाद में चीनी अधिकारियों ने निकाल-

बाहर कर दिया।

25-30 वर्ष की उम्र में तिब्बत की क्षेत्रीय राजधानी ल्हासा के डेपुंग और सेरा मठों में बौद्ध धर्म का अध्यापन करने के बाद ल्हुंडुप ने तिब्बत का व्यापक दौरा किया। बाद में 2008 में तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में बीजिंग की नीतियों और शासन के खिलाफ उठे क्षेत्रीय विद्रोहों के बारे में किताबें लिखी और प्रकाशित कीं। 04 दिसंबर, 2020 को ल्हुंडुप के परिवार को चीनी अधिकारियों ने उनके मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें केवल इतना पता चला कि उनका मुकदमा अभी भी लंबित है और उन्हें उनसे मिलने की अनुमित नहीं थी। सूत्रों ने कहा कि लुंडुप की पत्नी और एक बच्चा है।

2008 में चीन के तिब्बत और तिब्बती क्षेत्रों में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लेखकों, गायकों और कलाकारों को अक्सर हिरासत में लिया गया है तथा कई को लंबी जेल की सजा दी गई है। सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में तिब्बती भाषा अधिकार के लिए आंदोलन तिब्बती राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार, मठों और कस्बों में अनौपचारिक रूप से आयोजित भाषा पाठ्यक्रमों को आम तौर पर

'अवैध सभा' माना जाता है और पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए सांगेय कुंचोक द्वारा रिपोर्ट किया गया। तेनज़िन डिकी द्वारा अनुवादित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखित।

• लापता तिब्बती भिक्षु को सजा सुनाई गई, जेल भेजा गया - परिवार

रिनचेन त्सुल्ट्रिम पर;देश को विभाजित करने के लिए काम करने; का आरोप। यह आरोप अक्सर चीन की प्रमुख हान संस्कृति में तिब्बती संस्कृति को आत्मसात करने का विरोध करने वाले तिब्बतियों के खिलाफ लगाया जाता है। rfa.org, 24 जून, 2021

एक तिब्बती भिक्षु के परिजनों का कहना है कि भिक्षु को दो साल पहले 'देश को विभाजित करने' के लिए काम करने के संदेह में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में रखा गया। उसे एक बंद मुकदमे में सजा सुनाई गई थी और वह साढ़े चार साल की जेल की सजा काट रहा है। आरएफए को पहले बताया गया था कि 27 जुलाई, 2019 को 29 वर्षीय रिनचेन त्सुल्ट्रिम को सिचुआन के नगाबा (चीनी, आबा) काउंटी में सोशल मीडिया पर तिब्बती राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर शांतिपूर्वक अपने विचार व्यक्त करने के लिए हिरासत में लिया गया था। त्सुल्ट्रिम की बहन कुनसांग डोल्मा ने भारत निर्वासन के अपने घर से आरएफए को बताया कि इस साल की शुरुआत तक उसके परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। परिवार ने कहा कि 23 मार्च, 2021 को तिब्बत में मेरे परिवार को चीनी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि मेरे भाई रिनचेन त्सुल्ट्रिम को बिना निष्पक्ष सुनवाई के साढ़े चार साल की जेल की सजा दी गई थी और अब वह (सिचुआन के) मियांयांग जेल में बंद है।

डोल्मा ने कहा, 'चीनी अधिकारियों ने उन्हें 2019 में गिरफ्तार किए जाने से पहले

तिब्बती राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपने विचार और लेखन को व्यक्त करने के लिए तीन बार चेतावनी दी थी। एक बार तो उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए गए थे।' भारत में निर्वासन में रहने वाले एक तिब्बती ने आरएफए की तिब्बती सेवा को पहले ही बताया था कि निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के साथ त्सुल्ट्रिम के



जारी संपर्क उनकी गिरफ्तारी का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था। अलगाववाद, या 'देश को विभाजित करने के लिए काम करना' ऐसे कथित आरोप हैं जो तिब्बत की विशिष्ट राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को चीन की प्रमुख हान मूल की संस्कृति में आत्मसात करने की चीनी नीति के खिलाफ बोलने वालों पर चीनी अधिकारियों द्वारा आम तौर पर लगाए जाते हैं। तिब्बत में कई भिक्षुओं, लेखकों, शिक्षकों और संगीत कलाकारों को हाल के वर्षों में इन्हीं आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। संचार माध्यमों पर शिकंजा चीनी अधिकारियों ने तिब्बत क्षेत्र में सूचना प्रवाह पर कड़ाई से नियंत्रण जारी रखा है। यहां पर तिब्बतियों द्वारा सोशल मीडिया पर समाचार और राय पोस्ट करने और निर्वासन में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार तो चीन विरोधी प्रदर्शनों की खबरों के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तिब्बत के लिए अधिकार समूहों और अन्य विशेषज्ञों ने यह सूचना दी है। सेंसर और पुलिस के विशेष निशाने पर मोबाइल फोन पर साझा की गई दलाई लामा की तस्वीरें और तिब्बती भाषा के संरक्षण के लिए आह्वान करती हुई फोन कॉल्स होती हैं। तिब्बती स्कूलों में चीनी भाषा को शिक्षा की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित करने के सरकारी आदेशों के बाद से तिब्बती भाषा वहां खतरे में है। स्विट्जरलैंड में निर्वासन में रह रहे पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी गोलोक जिग्मे ने कहा कि आगामी 01 जुलाई से शुरू हो रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के शताब्दी समारोह के मद्देनजर अब तिब्बत और तिब्बती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

जिग्मे ने चीनी प्रांतों- सिचुआन, गांसु और किंघाई के सूत्रों के हवाले से कहा, 'जैसे-जैसे सीसीपी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ नजदीक आ रही है, वेबसाइटों तक पहुंच को कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।'

'किसी भी तरह के विद्रोही कृत्य में शामिल होने के संदेह में किसी को भी हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि चीनी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है।'

जिग्मे ने कहा कि पुलिस द्वारा रखी जा रही कड़ी निगरानी के परिणामों से भयभीत तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों से अब तिब्बत के अंदर के समाचार या अन्य जानकारी प्राप्त करना आम दिनों से भी अधिक कठिन हो गया है। ज्ञातव्य है कि लगभग 70 साल पहले चीन द्वारा बलपूर्वक एक पूर्व स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था और चीन में शामिल किया गया था। इसके बाद दलाई लामा और उनके हजारों अनुयायी भारत में निर्वासन में भाग गए और बीजिंग ने तिब्बत और पश्चिमी चीनी प्रांतों के तिब्बती आबादी वाले क्षेत्रों पर कड़ी पकड़ बनाए रखी। आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए सांगेय कुंचोक और लोबे द्वारा रिपोर्ट किया गया। तेनज़िन डिकी द्वारा अनुवादित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया।

• चीन ने निर्वासित तिब्बतियों से संपर्क करने के आरोप में तिब्बतियों को ड्रिरू में गिरफ्तार किया

tibet.net, 30 जून, 2021



निर्वासन में तिब्बतियों से संपर्क करने के लिए चीन ने दिरू में तिब्बतियों को गिरफ्तार किया।

धर्मशाला। तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के ड्रिरू काउंटी, नागचू में कई तिब्बती चीन द्वारातिब्बतियों को गैरकानूनी तरीके से कारावास में डालने की नीति के नवीनतम शिकार बन गए हैं। गिरफ्तारियां अप्रैल 2021 में हुईं और इसकी जानकारी तब हुई, जब एक तिब्बती ग्याजिन की पहचान की गई है। उस समय गिरफ्तार किए गए अन्य तिब्बतियों के नाम ज्ञात नहीं हैं। चीनी अधिकारियों ने चार बच्चों के पिता 44 वर्षीय ग्याजिन को निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से बात करने के कारण गिरफ्तार कर लिया। ग्याजिन मेरी गांव, त्सला टाउनशिप, ड्रिरू काउंटी, नाग्चु प्रिफेक्चर के रहनेवाले हैं। सूत्रों के अनुसार, ग्याजिन अक्सर अन्य तिब्बतियों को तिब्बती भाषा के अध्ययन और संरक्षण और एक-दूसरे के बीच एकता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने नाजुक तिब्बती पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया। पिछले एक दशक में, चीनी शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने ड़िरू काउंटी को उन क्षेत्रों में से एक बना दिया है, जहां चीनी शासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसलिए, यहां पर सुरक्षा विशेष रूप से कड़ी है और क्षेत्र के अंदर की स्थिति के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है। क्षेत्र में व्यापक निगरानी के कारण ड्रिरू से तिब्बत के बाहर तत्काल समाचार प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ड्रिरू से रिपोर्ट की गई ताजा खबर कुंचोक जिनपा की

मौत थी. जो चीनी जेल में यातना के कारण काल के गाल में समा गए। अगस्त 2020 में डिरू काउंटी में ही तीन बच्चों की 36 वर्षीया मां ल्हामो की भी चीनी हिरासत में यातना के कारण मृत्यु हो गई। चीनी नीतियों के विरोध में वर्षों से विरोध प्रदर्शन ड्रिरू प्राकृतिक संसाधनों से समृद्व है और अपने यार्त्सा गुनबू (कैटरपिलर कवक) संग्रह के लिए जाना जाता है जो अधिकांश स्थानीय तिब्बतियों के आय का मुख्य स्रोत बन गया है। तिब्बती स्वतंत्र रूप से यार्त्सा गुनबू के संग्रह में हाल ही में संलग्न हुए हैं। क्योंकि चीनी अधिकारियों ने इस उत्पाद को इकट्ठा करने की अवधि को 15 मई से 30 जून 2021 तक केवल एक महीना 15 दिनों की अवधि के लिए सीमित करने वाले नियमों का एक नया सेट तैयार कर दिया है। स्थानीय अधिकारी भी तिब्बती असंतुष्टों को इस अवधि के इतर यार्त्सा गुनबु संग्रह करने से मना कर दंडित करने के साधन के रूप में इस नियम का उपयोग करते हैं। ड्रिरू एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने कई वर्षों से लगातार चीनी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। 2010 में एक बांध बनाने के लिए आने का दावा करते हुए चीनी श्रमिकों को ड्रिरू लाया गया था, लेकिन वास्तव में उन्हें ड्रिरू के खनिज समृद्ध पवित्र नागल्हा दज़ांबा पर्वत पर खनन गतिविधियों में लगाया गया था। स्थानीय तिब्बतियों ने खनन का विरोध किया और अधिकारियों ने काम रोकने पर सहमति भी जता दी। मई 2013 में जब चीनी-सरकार से संबद्ध खनिक फिर से पवित्र पर्वत का दोहन करने के लिए आए, तो 4500 से अधिक तिब्बती खनन का विरोध करने के लिए एकत्र हो गए और विभिन्न चीनी सरकारी कार्यालयों में याचिकाएँ भी दायर कर दीं। हालांकि खनन विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले कई तिब्बतियों को बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पडे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सरकार ने एक राजनीतिक पुन: शिक्षा अभियान लागू करने का प्रयास किया। इसके तहत विशेष रूप से तिब्बतियों को अपनी छतों पर चीनी झंडे फहराने के लिए मजबूर किया गया। इस आदेश ने समस्या को और बढ़ा दिया क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अधिक विरोध- प्रदर्शन हुए और अधिक गिरफ्तारियां हुईं। 2013 के अंत में चीनी अधिकारियों ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। बाद के वर्षों में, स्थानीय अधिकारियों ने पहले के विरोध- प्रदर्शनों में भाग लेने के संदेह वाले तिब्बतियों को गिरफ्तार करना जारी रखा। चीनी अधिकारियों के मुख्य निशाने पर वे तिब्बती लोग भी थे. जिन पर ड़िरू में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी तिब्बत के बाहर भेजने का संदेह था।

अखिल भारतीय तिब्बत समर्थको के कोर ग्रुप – भारत ने सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के साथ अपनी पहली आभासी बैठक आयोजित की

tibet.net, 6 जून 2021



कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ के सदस्य के साथ वार्तालाब करते तिब्बत के सिक्यांग पेंपा छेरिंग।

नई दिल्ली। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़- इंडिया (सीजीटीसी-

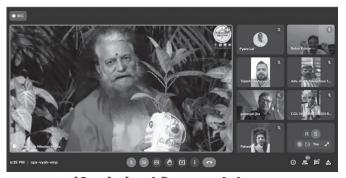
आई) के सदस्यों ने आज 6 जून को नवनिर्वाचित माननीय सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के साथ अपनी पहली आभासी बैठक की। बैठक का उद्देश्य औपचारिक रूप से सभी सीजीटीसी-आई सदस्यों का अभिवादन करना, अपेक्षित परिणामों, प्रगति के क्षेत्रों और आगामी गतिविधियों के परिणामों के बारे में आकलन और कोर समूह के कार्यों का समग्र मूल्यांकन पर विचार-विमर्श करना था। दो घंटे की लंबी बैठक की शुरुआत सबसे पहले सीजीटीसी-आई की अब तक की विकास यात्रा के बारे में परिचय से हुई। सीजीटीसी-आई की शुरुआत 2002 में 7 सदस्यों (1 राष्ट्रीय संयोजक और 6 सह-संयोजकों के साथ) के साथ हुई जिनकी संख्या २०२१ में २२ सदस्यों (१ राष्ट्रीय संयोजक, ४ राष्ट्रीय सह-संयोजक, १७ क्षेत्रीय संयोजक के साथ) तक पहुंच गई। ये सभी पदाधिकारी उन सभी संबंधित संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के तिब्बत समर्थक समूहों के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद, सदस्यों ने उन सभी प्रतिष्ठित सदस्यों का सम्मान करते हुए एक फोटो स्क्रीनिंग प्रस्तुत की, जिन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना की आधारशिला रखी और इसकी मशाल वर्तमान पदाधिकारियों को सौंपते समय तक इसकी लौ को जलाए रखा। बैठक में जयप्रकाश नारायण, मध् लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस, सत्य प्रकाश मालवीय, डॉ. एन.के. त्रिखा से लेकर बुधप्रिया थूल, निर्मला देशपांडे, सुंदरलाल बहुगुणा और ऐसी अनेक विभूतियों को श्रद्वांजलि दी गई।

सीजीटीसी-आई के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर.के. खिरमे ने अपने संबोधन में माननीय सिक्योंग श्री पेन्पा त्सेरिंग को औपचारिक रूप से बधाई दी। उन्होंने एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करने के लिए तिब्बती लोगों के ज्ञान की प्रशंसा की, जिन्होंने राजनीतिक ढांचे और सीटीए के प्रशासनिक कामकाज दोनों का ज्ञान हासिल किया है। श्री खिरमे ने कोर ग्रुप के पिछले कार्यों का सिंहावलोकन किया। इसमें कोर ग्रुप ने कहां तक हासिल किया था, उद्यम के दौरान कितनी विफलताएं सामने आईं और जरूरी पड़ने पर कहां तक इसने पुनर्निर्माण किया, का लेखा- जोखा था। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक भारतीयों की एकमात्र इच्छा है कि तिब्बत परम पावन 14वें दलाई लामा के जीवनकाल में स्वतंत्रता के प्रकाश को देखे और परम पावन गर्व से तिब्बत लौटें। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार ने माननीय सिक्योंग को बधाई दी और वर्तमान महामारी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कोर ग्रुप के सदस्यों की कार्य योजनाओं के विकास में उनका मार्गदर्शन मांगा। पश्चिमी क्षेत्र के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री अरविंद निकोस ने;चीनी सामानों का बहिष्कार; के अभियान का हवाला देते हए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हितों में बाधा डालने वाली व्यावहारिक कार्यप्रणाली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय सह-संयोजक श्री अमृत जोशी ने अपने गृह राज्य कर्नाटक से ताल्लुक

रखने वाले नेता और एक क्षम नेता के तिब्बतियों के सिक्योंग के रूप में चुने जाने पर दोहरी ख़ुशी व्यक्त की। श्री जोशी ने प्रो. समदोंग रिनपोछे के दृष्टिकोण और शब्दों को याद दिलाया, जिसमें श्री रिनपोछे ने कहा था कि;संबंधित कार्यों का निर्वाहन करते समय वह रणनीति में प्रतिबिंबित होना चाहिए।' राष्टीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्री पंकज गोयल; उत्तरी क्षेत्र-I के क्षेत्रीय संयोजक श्री फुंसोक लद्दाखी; उत्तरी क्षेत्र-द्वितीय के क्षेत्रीय संयोजक श्री ऋषि कुमार; पूर्व और मध्य यूपी के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुंदरलाल सुमन; पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्रीय संयोजक श्री रवि बख्शी; पूर्वी क्षेत्र- I के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी; पूर्वी क्षेत्र- II के क्षेत्रीय संयोजक श्री पेमा वांडा भूटिया; पूर्वी क्षेत्र-III की क्षेत्रीय संयोजक श्रीमती रूबी मुखर्जी; पूर्वीत्तर क्षेत्र- I के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता: उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्री नरेंद्र चौधरी: पश्चिमी क्षेत्र-I के क्षेत्रीय संयोजक श्री संदेश मेश्राम: पश्चिमी क्षेत्र-II के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. महेंद्र संघपाल: दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्री जे. पी. उर्स और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्री जैकब डेविड ने बैठक में भाग लिया और नए सिक्योंग को बधाई और शुभकामनाएं दीं। माननीय सिक्योंग श्री पेन्पा त्सेरिंग ने अपने संबोधन में सीजीटीसी-आई के सदस्यों द्वारा दिए गए सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने तिब्बती मुद्दे पर लगातार विश्वास और समर्थन दिखाने के लिए विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद दिया और वर्षों से तिब्बत पर राष्ट्रव्यापी समर्थन जारी रखने के लिए उनकी सराहना की। इसके अलावा सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में तिब्बती लोगों के लिए अपनी सेवा की राह में आने वाली चुनौतियों और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नेतृत्व की प्रतिबद्धताओं को दोहराया, जिसमें चीनी सरकार के साथ रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करना, वैश्विक स्तर पर तिब्बत मुद्दे के प्रचार प्रसार करने में 25 देशों में लगे युवा तिब्बती समुहों की क्षमता का उपयोग करना शामिल है। उन्होंने कोर ग्रुप के सदस्यों को याद दिलाया कि समय महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही उन्हें लंबे समय से चले आ रहे चीन-तिब्बत संघर्ष के समाधान में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उप समन्वयक श्री तेनज़िन जॉर्डन ने उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। आईटीसीओ के श्री चोनी त्सेरिंग और श्री जामयांग चोफेल ने तकनीकी सहायता प्रदान की। कोर ग्रुप के कुछ सदस्य जिनमे, उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीय सह-संयोजक डॉ. के.सी. अग्निहोत्री; उत्तरी क्षेत्र-III के क्षेत्रीय संयोजक श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल; उत्तर पूर्व क्षेत्र- II के क्षेत्रीय संयोजक श्री लोबसंग जेनचेन और उत्तर पूर्व क्षेत्र- III के क्षेत्रीय संयोजक श्री एस. प्रेमानंद शर्मा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

आर्यभूमि और पृथ्वी के तीसरे ध्रुव का संरक्षण: विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार

tibet.net, 7 जून, 2021



वेबिनार मे जुड़े स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज।

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने वानिकी और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व पर केंद्रित एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सामाजिक जरूरतों और विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए गए पर्यावरणीय शोषण के बारे में बोलकर वेबिनार की शुरुआत की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धरती माता को बचाना प्रकृति को बचाना है और प्रकृति के संरक्षण से हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। भारत में कोविड -19 की सबसे हालिया और विनाशकारी लहर का उदाहरण देते हुए स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रतिभागियों से कहा कि जब तक हम प्रकृति और उसके संसाधनों के मूल्यों को बनाए नहीं रखेंगे, हमें ऑक्सीजन खोजने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा जैसा कि हाल ही में भटकना पड़ा है।

उन्होंने विलुप्त हो रहे दुर्लभ वनस्पतियों को लेकर शोक व्यक्त किया और पवित्र पीपल, बरगद, जामुन, नीम जैसे फलों और औषधीय तत्वों वाले वृक्षों को बड़े पैमाने पर लगाने का आह्वान किया।महाराष्ट्र में आयकर आयुक्त डॉ. पतंजिल झा ने निदयों पर विशिष्ट वृक्षारोपण के अपने अनुभव साझा किए जो जल संरक्षण में अत्यधिक मदद कर सकते हैं। उन्होंने आगे पवित्र तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय के पौधारोपण पर जोर दिया। डॉ. झा ने विशेष रूप से किसानों से बहु-परत खेती, स्व-पहल और सतत विकास परियोजनाओं का अभ्यास करने का आग्रह किया।

इस विषय पर एक प्रख्यात वक्ता उत्तराखंड सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. रघुवीर सिंह रावत ने रासायनिक खेती से जैविक खेती में व्यावहारिक बदलाव पर जोर दिया। यद्यपि विभिन्न स्तरों पर कई वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण से अधिक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण की देखभाल और सुरक्षा है। आयुर्वेद सिंहत कई प्राचीन ग्रंथ 10,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के पेड़ों को दशति हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण हैं। बीटीएसएस के संगठन सचिव श्री एन.पी.एस. भदौरिया ने कहा कि भारत आर्यों की भूमि रही है, जहां कभी दूध और घी की नदियां बहती थीं, लेकिन अब यह भूमि अनापेक्षित प्राकृतिक आपदाओं, सुखा, बाढ़ और अकाल का सामना कर रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह सब अज्ञानता और सांस्कृतिक विचलन के कारण होता है। इसे बचाने का एकमात्र तरीका जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि बीटीएसएस भारत के प्राकृतिक संसाधनों, सीमाओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तिब्बत और तिब्बती लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री भदौरिया ने बीटीएसएस के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री हेमेंद्र तोमर के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें भारत माता और तिब्बत के साथ इसकी सांस्कृतिक आत्मीयता की सेवा करने का अवसर दिया।

बीटीएसएस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर आईटीसीओ के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने इस अवसर पर दुनिया भर में एक-दूसरे पर आश्रित प्रकृति पर अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण को साझा करते हुए बताया कि कैसे किसी की विकास परियोजना दूसरों की पारिस्थितिकी और आजीविका में बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट चीन की स्व-उन्मुख आर्थिक परियोजनाएं जैसे कि तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर अत्यधिक बांध और जलविद्युत परियोजनाएं अनिगत लोगों और भारत सहित निचले क्षेत्र के देशों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा कि 1950 के दशक में तिब्बत में आधिकारिक तौर पर 22 छोटे- बड़े बांध थे जो सन 2000 तक बढ़कर 22,000 से अधिक बन गए। तिब्बत में 1998 तक 50% से अधिक जंगलों को काट दिया गया था और शेष बचे 50 प्रतिशत पर अब बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

'तिब्बत एशिया का जल मीनार और दुनिया का तीसरा ध्रुव है।' हालांकि, उन्होंने कहा कि तिब्बत की नाजुक पारिस्थितिकी पहले से ही अभूतपूर्व दर से घट रही है। उन्होंने कहा कि अपने 46000 निर्दिष्ट ग्लेशियरों में से 8790 से अधिक ग्लेशियर पिघलकर कथित तौर पर झील या तालाब बन गए हैं और इनमें से 204 से अधिक झीलें किसी भी समय अभूतपूर्व आपदा का कारण बन सकती हैं।

श्री त्सुल्ट्रिम ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे मौजूदा चुनौतियों पर बात करें जो निकट भविष्य में तिब्बत और तिब्बती लोगों और भारत के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट चीनी सरकार के अन्याय के खिलाफ तिब्बती संघर्ष को अटूट समर्थन के लिए बीटीएसएस को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त की। टेरायर्स फाउंडेशन के संस्थापक और बीटीएसएस के पर्यावरण विंग के राष्ट्रीय प्रभारी कर्नल (सेवानिवृत्त) एच.आर.एस. राणा ने दोहराया कि बीटीएसएस और अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों को संयुक्त रूप से प्रकृति और उसके संसाधनों के संरक्षण पर इस वास्तविकता को जमीन पर उतारना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से युवा प्रतिभागियों से आगे आने और इसकी लंबी उम्र और स्थिरता को बनाए रखने की ध्वजा थामने का आग्रह किया। कर्नल राणा ने लहाख, मसूरी और बेंगलुरु में इको टास्क फोर्स में अपने अनुभवों को याद किया, जहां नियोजित प्रयासों और उदात्त विश्वास ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को

सफलतापूर्वक संरक्षण किया था।

इस कार्यक्रम की मेजबानी डीएवी कॉलेज, जालंधर के डॉ. राहुल तोमर ने की, जिन्होंने इस कार्य में अपने पेशेवर अनुभव को दर्शाया और वर्घुअल वर्ल्ड में बड़े दर्शकों के लिए इसके महत्व और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए वक्ताओं द्वारा सुझाए गए प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों को 15 जून 2021 को आगामी वेबिनार के बारे में भी बताया, जिसमें गालवान घाटी के शहीदों को याद किया जाएगा और चीनी दोहरी मानसिकता के असली चेहरे को उजागर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। श्री आशुतोष गुप्ता और विजय मान ने कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष को संचालित किया। गूगल पर दुनिया भर में तकनीकी खराबी के कारण, 5 जून 2021 शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रस्तावित गूगल मीट को शाम 6 बजे पुनर्निर्धारित किया गया और उसी दिन रात 9 बजे तक जारी रखा गया।

• भारत-तिब्बत सीमा पर गलवान घाटी में भारतीय सेना के शहीदों का सम्मान

tibet.net, 16 जून, 2021



भारत के पूर्व मेजर जनरल निलेन्द्र कुमार।

दिल्ली। आज 16 जून को गलवान घाटी में हुए उस हादसे की पहली बरसी है जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के सैनिकों के हमलों से भारत की सीमा की रक्षा करते हुए 20 बहादुर भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस दिन को याद करने के लिए भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), दिल्ली ने गलवान के सभी बहादुर जवानों को सम्मानित करते हुए 'भारत-तिब्बत सीमा पर भारतीय सेना के शहीदों का सम्मान' शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया।

अतिथि वक्ताओं में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के उत्तरी क्षेत्र- I (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) के क्षेत्रीय संयोजक श्री फोन्सोक लद्दाखी; भारत तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एवीएसएम, वीएसएम, पूर्व जेएजी सेना (प्रो.) नीलेंद्र कुमार; कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र- I (असम और मेघालय) के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता; नेताजी बोस रक्षा अकादमी (एनबीडीए, कोयंबटूर और समन्वयक, फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत (एफओटी), कोयंबटूर के निदेशक प्रो. वी. अंटो शामिल थे।

श्री फोन्सोक लद्दाखी ने सभी 20 वीर शहीदों के नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजिल दी। उन्होंने कहा कि हमें देश की रक्षा के लिए उनके बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। श्री फोन्सोक ने उल्लेख किया कि गलवान की घटना युद्ध नहीं थी; बल्कि यह कम्युनिस्ट चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसने के लिए एक बर्बर कार्य था और भारतीय जवानों पर लोहे की छड़, कांटेदार तारों, स्पाइक्स, पत्थरों आदि से हमला किया था। उन्होंने कहा कि एक भारतीय सैनिक देश की रक्षा

करने की शपथ लेता है, न कि कम्युनिस्ट चीन के सैनिकों की तरह, जैसा देखा गया, आक्रामकता की शपथ लेता है।

श्री फोन्सोक ने गर्व से उल्लेख किया कि वह लद्दाख से आते हैं जहां से सड़क गलवान घाटी की ओर जाती है और लद्दाख बहादुर दिलों की भूमि है जहां जवान और नागरिक दोनों सीमा की रक्षा करते हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि दुनिया में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अपने आप में एक समस्या है, समाधान नहीं। परम पावन दलाई लामा की सलाह के अनुसार संवाद और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया जाना चाहिए।

मेजर जनरल (प्रो.) नीलेंद्र कुमार ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रेरणास्पद बताया और कहा कि इतिहास उन्हें उनके बलिदानों के लिए याद रखेगा। उन्होंने कहा कि करीब 4 घंटे तक चले गलवान संघर्ष को भारत-चीन संघर्ष के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह समझने की जरूरत है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बीजिंग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की आलोचना और उसके विरोध की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया है। गलवान घटना के संबंध में प्रेस सेंसरशिप और सोशल मीडिया सेंसरशिप लगी हुई है। यह पीएलए के आलोचकों का मुंह बंद करने का प्रयास है। चीन के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है।

मेजर जनरल ने आगे रक्षा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को साझा करते हुए कहा कि भारत को चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने क्षेत्र को कम्युनिस्ट चीनी आक्रमण से बचाने के लिए अपने बुनियादी रक्षा ढांचे का विकास करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में नौ विशिष्ट प्रस्तावों की ओर इशारा किया। ये नौ विशिष्ट प्रस्ताव हैं- (i) रक्षा मामलों और निर्णयों के लिए एक विशेष समिति; (ii) सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना और संचार विकास; (iii) आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है लेकिन देश की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करते हुए; (iv) उचित राजनयिक तरीके से सीमा वार्ता; (v) हमारे रक्षा प्रशिक्षण सिद्धांत में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए; (vi) संचालन योजना को कुशल और परिणामोन्मुखी बनाया जाना; (vii) भारतीय सेना में आईटीबीपी और विकास बटालियनों को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम; (viii) भविष्य में किसी भी लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई और अभिनव रणनीति और (ix) सुरक्षा के लिहाज से भारत की उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमाएं चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।

अपने संबोधन का समापन करते हुए मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार ने कहा कि चीन ने महसूस किया है कि वह भारत की सुरक्षा के संबंध में अब और धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। चीन का हर संभव तरीके से मुकाबला करने के लिए भारत के लिए विश्व स्तरीय शक्ति हासिल करने का भी समय आ गया है।

श्री सौम्यदीप दत्ता ने अपने संबोधन में 1962 के चीन-भारत युद्ध से लेकर गलवान संघर्ष तक के सभी शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजिल अर्पित की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन भारत के खिलाफ एक नहीं, बल्कि तीन प्रकार के युद्ध छेड़ता है। ये भौतिक, दार्शनिक और पारिस्थितिक युद्ध हैं। भारत-तिब्बत सीमा पर शारीरिक युद्ध, भारत से उत्पन्न बौद्ध दर्शन को नष्ट करके दार्शनिक युद्ध और ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांधों का निर्माण करके पारिस्थितिक युद्ध। जिसे तिब्बत में त्संगपों के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत को प्रभावित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लोगों को यह जानना चाहिए कि यह भारत-चीन सीमा नहीं है, यह भारत-तिब्बत सीमा है। हमने कभी चीन को अपना पड़ोसी नहीं माना, तिब्बत हमारा पड़ोसी है। चीन ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और अब वह पूर्वीत्तर भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा है, उसे चीन द्वारा नष्ट किया जा रहा है। इसने ब्रह्मपुत्र पर एक, दो या तीन नहीं बल्कि कई बड़े बांध बनाए हैं जो अरुणाचल प्रदेश, असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए विनाशकारी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बौद्ध धर्म भारत की संस्कृति है। इसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में नष्ट कर दिया था लेकिन तिब्बत में इसे संरक्षित रखा गया था। चीन वर्तमान में तिब्बत में इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है इसलिए इसे भारत में संरक्षित करना महत्वपूर्ण है जहां यह फल-फूल रहा है।

श्री दत्ता ने निष्कर्ष में तिब्बत के संबंध में पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से नागरिक समाजों में जागरूकता पैदा करने के महत्व, भारत के लिए इसके महत्व और चीन के बुरे इरादों पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके संबंध में नागरिक समाज आंदोलन को मजबूत किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि - (i) तिब्बत हमारा पड़ोसी है, (ii) भारत चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और (iii) चीन एक आक्रामक देश है। उसने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और जो तिब्बत के साथ हुआ था वह पूर्वोत्तर भारत के साथ हो सकता है।

प्रो. वी. अंटो ने सीटीए की तुलना ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित भारत की निर्वासित सरकार से की। सीटीए द्वारा लागू किए जा रहे अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित मध्यम मार्ग के रुख की सराहना करते हुए प्रो. अंटो ने यह भी संकेत दिया कि न केवल तिब्बतियों बल्कि भारत को भी कम्युनिस्ट चीन का सामना करने के लिए सैन्य रूप से तैयार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बत की आवाज को बढ़ाना दूसरे शब्दों में चीन के खिलाफ भारत के मोर्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने सीसीपी सरकार की सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री सेतु दास और फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत (एफओटी) के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों को भी याद किया। प्रो. अंटो ने 2019 में शी जिंगपिंग की पिछली भारत यात्रा के दौरान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज व्यक्त करने वाले तिब्बती छात्रों के साथ स्थानीय भारतीय पुलिस (महाबलीपुरम में) के व्यवहार के तरीके पर भी अपना विरोध दर्ज कराया।

वेबिनार के दौरान गलवान के 20 वीर जवानों को सम्मान देने के लिए बीच में 'माँ' शीर्षक से एक श्रद्धांजलि गीत प्रसारित किया गया। बाद में, कुछ प्रतिभागियों ने अतिथि वक्ताओं के साथ अपने विचार और मत साझा किए।

आईटीसीओ दिल्ली के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने भारत के उन बहादुर जवानों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पर देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।

आईटीसीओ दिल्ली के उप समन्वयक श्री तेनज़िन जॉर्डन ने परिचयात्मक टिप्पणी दी जिसमें उन्होंने इस दिवस के महत्व और जवानों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बारे में बताया।

वेबिनार के अंत में प्रतिभागियों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

• भारत तिब्बत समन्वय संघ ने विश्व शरणार्थी दिवस पर तिब्बती पुनर्जागरण का जश्न मनाया

tibet.net, 22 जून, 2021



दिल्ली। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने शरणार्थियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुरूप भारत की नीतियों की व्याख्या करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन चर्चा की।

कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि अलवर, राजस्थान के माननीय सांसद श्री महंत बालक नाथ योगी ने टिप्पणी की कि परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती शरणार्थी समुदाय आज भारतीय परिवार का हिस्सा बन गया है।

उन्होंने कहा कि तिब्बती हमेशा परम पावन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं और परम पावन की महान इच्छाओं पर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और खुशी के लिए उनकी दूरदर्शी दृष्टि का उल्लेख करने की तो जरूरत ही नहीं है।

सांसद ने भारतीय समाज के ताने-बाने को समृद्ध बनाने, इसके मूल्यों और ज्ञान की रक्षा करने में तिब्बती लोगों के योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी ने कहा कि बीटीएसएस तिब्बती लोगों की गिरमा और पहचान को बहाल करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और इसके लिए वैश्विक प्रयास की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग भारतीय परिवार का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्राचीन काल से भारतीय दिमाग और दिलों का दोहन करने में अनुकरणीय योगदान दिया है।

रेव संत सुनील कौशल ने संकेत दिया कि भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' के रूप में धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना मानव अधिकार के सभी कारणों को अपनाया है। इस अर्थ में, भारत की इस भूमि में विभिन्न प्रकार के धर्मों और संप्रदायों को फलने- फूलने का मौका मिला है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व कार्यकारी सचिव श्री रोहित पांडेय ने उन कानूनों और सामान्य नियमों और विनियमों को रेखांकित किया जो भारत की भूमि में शरण लेने वाले शरणार्थियों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हैं।

उन्होंने कानूनों को पेश करते हुए उनके निष्पादन से जुड़े महत्व और चुनौतियों, यूएनएचसीआर द्वारा स्थापित अधिकारों और कर्तव्यों और भारत सरकार के दृष्टिकोण के आधार पर शरणार्थी की व्याख्या करते हुए उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी।

पूर्व मेजर जनरल (प्रो.) नीलेंद्र कुमार ने जोर देकर कहा कि बीटीएसएस तिब्बतियों के लिए एक शक्तिशाली मंच है जिसने तिब्बतियों को सबसे मजबूत सहयोगी के तौर पर लगातार समर्थन दिया है। यद्यपि भारत कई अन्य शरणार्थियों की मेजबानी करता है जो कानूनी रूप से या अन्यथा देश में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन भारत और उसके लोग हर संभव तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई में तिब्बती भाइयों और बहनों की भावना को बढावा मिले।

आईटीसीओ के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने तिब्बतियों के लिए चर्चा के महत्व को स्वीकार किया जो 'वैश्विक स्तर पर लाखों अन्य लोगों के समान अनुभव साझा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वे आज तक राजनीतिक शरणार्थी बने हुए हैं।

• कनाडा के 'पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' ने सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग के साथ तिब्बत दिवस मनाया

tibet.net, 14 जून, 2021



वेबिनार मे जुड़े कनाडा के सांसद।

वाशिंगटन डीसी। कनाडा के 'पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत (पीएफटी)' ने 14 जून को तिब्बत मुद्दे के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए सिक्योंग श्री पेन्पा त्सेरिंग को सम्मानित करने के लिए 'सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग के साथ तिब्बत दिवस' का आयोजन किया।

सिक्योंग और पीएफटी के बीच यह पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक का संचालन सांसद आरिफ विरानी ने किया और इसमें चार अन्य सांसदों- गार्नेट जेनुइस, जेम्स मैलोनी, लैरी बैगनेल और डेविड स्वीट ने भाग लिया।

तिब्बत-वाशिंगटन डीसी का कार्यालय के प्रतिनिधि नोडुप त्सेरिंग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव, कनाडा-तिब्बत समिति के अध्यक्ष और निदेशक, तिब्बतन एसोसिएशनों के अध्यक्ष और कनाडा में कई तिब्बती गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

कनाडा के पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के अध्यक्ष सांसद आरिफ विरानी ने तिब्बती भाषा में सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग का आधिकारिक रूप से स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'हम बहुत प्रसन्न हैं और आपको तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं और यह भी कि हम आपके साथ अच्छे कामकाजी संबंध रखने के लिए बहुत उत्सुक हैं।'

उन्होंने सीटीए के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, एक प्रतिबद्धता जो उन्होंने परम पावन दलाई लामा से की थी और जिसे उन्होंने अनिवार्य रूप से 'यह सुनिश्चित करने के विचार के रूप में वर्णित किया कि कनाडा का ध्यान और दुनिया का ध्यान तिब्बत की जमीन सहित तिब्बत पर रहेगा।'

इस लक्ष्य की दिशा में अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का हवाला देते हुए उन्होंने रिसिप्रोकल एक्सेस ऐक्ट (पारस्परिक पहुंच अधिनियम) सिहत कुछ पहलों का प्रस्ताव दिया, जो पारस्परिकता के राजनियक सिद्धांत पर आधारित है, जो कि कनाडाई प्रतिनिधियों को तिब्बत और पीआरसी तक उसी तरह की पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करेगा जैसा कि चीनी प्रतिनिधियों को कनाडा में प्रवेश करने पर प्राप्त होता है।

सांसद विरानी ने उन दो प्रस्तावों का उल्लेख किया जिनका पीएफटी कनाडा वर्तमान में समर्थन करता है। पहला मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन और दूसरा चीन-तिब्बत वार्ता। ये दोनों प्रस्ताव क्रमश - सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स में लंबित हैं। सभी सांसदों ने सिक्योंग श्री पेन्पा त्सेरिंग का स्वागत किया और चीन-तिब्बत संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए सहयोगात्मक प्रयास में उनके साथ काम करने का आश्वासन दिया।

सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने सभी सांसदों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और तिब्बत के लिए वैश्विक समर्थन के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं में से एक है- वैश्विक समर्थन प्रयासों का अनुकूलन करना। उन्होंने कहा, 'हमारे पास लगभग 25 विभिन्न देशों में रह रहे तिब्बतियों की क्षमता है, जो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी प्रणाली को समझते हैं और देश में उन नेताओं के साथ काम करते हैं।'

इस संबंध में, सिक्योंग ने कहा कि उन्हें कनाडा से बहुत उम्मीद है कि वह एक उदाहरण स्थापित करेगा और तिब्बत मुद्दे का प्रचार करने को बढ़ावा देगा।

हालांकि, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां 'कुछ मुद्दों को ठोस बनाने' के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, जिसे तिब्बती प्रशासन आने वाले समय में उठाने का इच्छुक होगा।

इंटर्निशिप कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए सिक्योंग ने कहा कि यह ऐसी चीज है जिसकी उन्होंने लगातार सराहना की है और टिप्पणी की कि कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले तिब्बती युवा अब समुदाय के योगदानकर्ता सदस्य बन गए हैं।

ओओटी-डीसी के प्रतिनिधि नोदुप त्सेरिंग ने इस वर्ष के तिब्बत दिवस में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सांसद आरिफ विरानी और कनाडा के पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने 2018 और 2019 में दो तिब्बत दिवस कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का उल्लेख किया और इसे 'सबसे अधिक उपयोगी और प्रभावी युवा नेतृत्व कार्यक्रम में से एक' के रूप में वर्णित किया।

हर साल पीएफटी हिल (मई और जून) पर सात सप्ताह के पीएफटी-कनाडा इंटर्निशिप कार्यक्रम की मेजबानी करता है और इंटर्निशिप कार्यक्रम के अंत में वे हिल पर वार्षिक पीएफटी 'ल्हाकर' कार्यक्रम की मेजबानी करते हैं। जिसमें हमारे पीएफटी सदस्य, प्रशिक्षु, विशेष अतिथि, तिब्बती समुदाय के सदस्य, मित्र और समर्थक शामिल होते हैं। दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण पीएफटी पिछले दो वर्षों से इंटर्निशिप कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सका है।

चोगकी ने 'हिल्स पर तिब्बत दिवस' बुधवार को ही क्यों मनाया जाता है, इस बारे में विवरण दिया। उन्होंने समझाया कि असल में कनाड़ा के मानद नागरिक परम पावन दलाई लामा का जन्म बुधवार को हुआ था, इसलिए तिब्बतियों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। कई वर्षों से, यह तिब्बती पहचान और संस्कृति के सभी पहलुओं को अपनाने के लिए एक विश्वव्यापी गैर-प्रतिरोध आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

- तिब्बत कार्यालय, वाशिंगटन डीसी द्वारा प्रस्तुत

• हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में दलाई लामा स्ट्रीट का उद्घाटन

tibet.net, 2 जून 2021



हंगरी के मेयर क्रिस्ज़टीना बरन्यिक।

जिनेवा। 02 जून 2021 को बुडापेस्ट के मेयर श्री गेरगेली कराकोनी और बुडापेस्ट 9वें जिले की मेयर सुश्री क्रिस्ज़टीना बरनी ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट शहर में दलाई लामा स्ट्रीट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही तीन सड़कों के नाम बदल दिए गए हैं। दो अन्य सड़कों- उग्यूर शहीद स्ट्रीट को फ्री हांगकांग स्ट्रीट और बिशप हसीह सी को कुआंग स्ट्रीट के रूप में नामकरण किया गया।

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा की ओर से बुडापेस्ट में रह रहे एक तिब्बती त्सेवांग थिनले नामग्याल और लंबे समय से तिब्बत समर्थक रहे तिब्बत प्रेस न्यूज़ के हेंड्री टिबोर से अनुरोध किया गया था कि वे महापौरों को पारंपरिक तिब्बती स्कार्फ और तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज भेंट करें और एकजुटता के संदेश वाले इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दें।

हंगेरियन सरकार ने हाल ही में 2024 तक हंगरी में एक चीनी विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण को लेकर चीन के साथ एक विवादास्पद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हंगरी के इस कदम के खिलाफ देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। हंगरी के लोग इस कदम को हंगरी में चीनी सरकार के प्रभाव और नियंत्रण बढाने के कदम के रूप में देखते हैं।

इसी तरह, पिछले हफ्ते संसदीय सत्र के दौरान कानूनविद् सेज़ल बनिडेट ने चीन के साथ हंगरी सरकार के विवादास्पद समझौते पर निराशा व्यक्त की और परियोजना के जोखिमों पर सवाल उठाया। इसमें देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रतिबंध शामिल हैं। विधायक ने सरकार से फुडन परियोजना को तुरंत रोकने का आह्वान किया।

उद्घाटन भाषण में, बुडापेस्ट के मेयर श्री गेरगेली कराकोनी और बुडापेस्ट 9वें जिले की मेयर सुश्री क्रिस्ज़टीना बरनी ने चीन की ऋण-जाल कूटनीति और हंगरी सहित लोकतांत्रिक देशों में चीनी अलोकतांत्रिक प्रभाव के विस्तार पर चिंता व्यक्त की।

सड़कों का नाम बदलने की कार्रवाई को चीन के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े तिब्बतियों, उग्यूर, हांगकांग और चीन के सभी मानवाधिकार रक्षकों को श्रद्धांजिल के रूप में माना जाता है। इसे चीनी विश्वविद्यालय के निर्माण पर हंगेरियन सरकार के समझौते के खिलाफ एक कदम के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि नामित सड़कें प्रस्तावित चीनी बुनियादी ढांचा परियोजना के नियोजित

स्थल के चारों ओर हैं।

बुडापेस्ट के पहले जिले के उप महापौर श्री फेरेंक गेलेंसर ने तिब्बत में 17 सूत्रीय समझौते और 70 वर्षों के उत्पीड़न को चिह्नित करने वाला तीन दिवसीय आभासी कार्यक्रम 'चाइना पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन एंड नन-कंप्लायंस (चीन की मुक्ति की राजनीति और उसकी अवज्ञा)' शीर्षक से एक पैनल चर्चा के दौरान हंगरीचीन अवसंरचनात्मक परियोजना पर भी चिंता व्यक्त की थी, जिसमें तिब्बत और हांगकांग से समानताएं चित्रित की गई थीं।

चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे की हंगरी यात्रा के दौरान श्री फेरेंस गारेंसर ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में तिब्बती राष्ट्रीय झंडे भी फहराए थे। उन्होंने बुडापेस्ट के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन हॉल में तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज और एक विरोध बैनर लगाया जिसमें चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत पीड़ित लोगों के लिए न्याय की मांग की गई, जिसमें उग्यूर मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे।

तिब्बत ब्यूरो जिनेवा ने महापौरों को इस तरह की एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया और संयुक्त राष्ट्र सिहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत, पूर्वी तुर्केस्तान, हांगकांग और चीन के कब्जे वाले अन्य सभी क्षेत्रों में दयनीय मानव अधिकार की स्थिति के खिलाफ खडे होने का आह्वान किया।

• डेनमार्क में चीन के राजदूत, फेंग टाई को सेंट्रल कोपेनहेगन में एक बैठक स्थल के बाहर विरोध का सामना करना पड़ा

tibet.net, 21 जून 2021



डेनमार्क मे चीनी राजदूत तिब्बती समर्थक का सामना करते हुए।

लंदन। डेनमार्क के सेंट्रल कोपेनहेगेन में उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब डेनमार्क में चीनी राजदूत फेंगे टाई के साथ हो रही बैठक के स्थल के बाहर अचानक चीनी राजदूत को प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ गया।

18 जून को डेनमार्क में तिब्बत समर्थक समूह ने डेनिश चाइना-क्रिटिकल सोसाइटी के साथ मिलकर सार्वजनिक राजनीतिक त्योहार, फोल्केमोडेट (पीपुल्स मीटिंग) के अवसर पर डेनमार्क में चीन के राजदूत मिस्टर फेंग टाई द्वारा सेंट्रल कोपेनहेगन में राजनीतिक मीडिया अल्टिंगेट को एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शन शुरू कर दिया।

तिब्बत, पूर्वी तुर्केस्तान, हांगकांग और चीन में चीनी दमन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी गुप्त रूप से तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज के साथ साक्षात्कार स्थल के बाहर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मिस्टर एंबेसडर के सामने फ्री तिब्बत, फ्री हांगकांग, फ्री चाइना जैसे नारे लगाए।

• कनाडा ने 43 देशों के साथ तिब्बत पर गंभीर चिंता जताई; झिंझियांग जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अनुमित देने को चीन से आह्वान किया

tibet.net, 22 जून, 2021



तिब्बत मे हो रहे मानवाधिकार के हनन के विरोध मे कनाडा और अन्य ४३ राष्ट्रय।

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 47वें सत्र के दौरान कनाडा समेत 44 देशों की ओर से एक क्रॉस-रीजनल संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें तिब्बत, पूर्वी तुर्केस्तान (चीनी: झिंझियांग) और हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और चीन से संयुक्त राष्ट्र को झिंझियांग तक जाने की अनुमित देने का आह्वान किया गया। आज, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर संवादात्मक संवाद के दौरान, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में कनाडा के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि लेस्ली ई. नॉर्टन ने क्रॉस-रीजनल संयुक्त वक्तव्य दिया।

संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने 21 जून को वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए उम्मीद जताई कि चीन इस साल झिंझियांग तक उनकी सार्थक पहुंच की अनुमित देगा। जिनेवा में चीनी मिशन ने कल उल्लेख किया कि उच्चायुक्त की यात्रा को 'दोस्ताना' माना जाएगा, न कि किसी 'जांच' के लिए की गई यात्रा। मिशन ने फिर से हांगकांग और झिंझियांग के मुद्दों को 'आंतरिक मामला' कहा और अपील की कि उसकी 'संप्रभुता' में हस्तक्षेप करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

झिंझियांग तक सार्थक पहुंचने की अनुमित देने के आह्वान का समर्थन करते हुए संयुक्त बयान में कहा गया है, 'हम चीन से आग्रह करते हैं कि वह उच्चायुक्त सहित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को झिंझियांग तक तत्काल, सार्थक और बाधारहित पहुंच की अनुमित दे और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर सिमिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करे। झिंझियांग से संबंधित सिफारिशों में उग्यूरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की मनमानी नजरबंदी को समाप्त करना शामिल है।

संयुक्त बयान में झिंझियांग में दस लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया। इसने यातना, जबरन नसबंदी, यौन नसबंदी, यौन और लिंग आधारित हिंसा आदि की रिपोर्टीं का भी उल्लेख किया गया है।

बयान देनेवाले देशों ने तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की और चीन से मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया। बयान देनेवाले 44 देशों में संयुक्त राष्ट्र के चार क्षेत्रीय समूहों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा, पूर्वी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, कैरिबियाई और एशिया और प्रशांत समूह के देश शामिल हैं।

जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो ने कनाडा के नेतृत्व में 44 देशों के क्रॉस-रीजनल संयुक्त बयान का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त से तिब्बत में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया है।

सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ: अत्याचारों की पराकाष्ठा

5 जून, 2021, tibet.net, येशी दावा

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की 100वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय सिमित के प्रचार विभाग 3/- ने 24 मार्च को एक लोगो (नीचे चित्र) जारी किया। हालांकि, मेरे जैसे तिब्बती शरणार्थी जो पीढ़ियों से सीसीपी के शिकार रहे हैं, के लिए जश्न मनाने लायक कोई बात नहीं है। फ्रीडम हाउस की नवीनतम रिपोर्ट ने तिब्बत को दुनिया में सबसे कम मुक्त देश के रूप में चिह्नित किया है। इस लिहाज से अकेले सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ तिब्बतियों के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में, सीसीपी का इतिहास और वर्तमान प्रक्षेपवक्र इस बात का एहसास कराता है कि इसका अस्तित्व क्यों बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।

सीसीपी का तिब्बत पर कब्जा



परम पावन दलाई लामा का भारत पलायन। फोटो सौजन्यः केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का तिब्बती संग्रहालय, धर्मशाला। सीसीपी ने 23 मई 1951 को तिब्बत के साथ तथाकथित 17 सूत्रीय समझौता किया और पेकिंग (अब बीजिंग) में दबाव के तहत न्गापो नगावांग जिग्मे के नेतत्व में तिब्बती प्रतिनिधियों को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। सीसीपी ने दावा किया है कि तिब्बत तब से चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है। सीसीपी का नवीनतम श्वेत पत्र जिसका शीर्षक '1951 से तिब्बत-मुक्ति, विकास और समृद्धि' है, को व्यापक रूप से तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति को विकृत करने और तथाकथित '17 सूत्री समझौते' को वैध बनाने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जाता है - जिसे मैंने 'चीन का तिब्बत पर श्वेत पत्र - एक काला झूठ' शीर्षक पत्र में खारिज करने का प्रयास किया था। इस तथाकथित समझौते के बाद सीसीपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपनी क्रूर ताकतों का इस्तेमाल किया, जो परम पावन चौदहवें दलाई लामा को उनके अपहरण की चीनी साजिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके कारण हजारों निर्दोष तिब्बतियों का नरसंहार हुआ। 10 मार्च 1959 को विद्रोह के बाद, परम पावन 80,000 तिब्बतियों के साथ तिब्बत से भाग गए और भारत में राजनीतिक शरण मांगी। ऐसा माना जाता है कि 1940 के दशक से सीसीपी ने 12 लाख से अधिक तिब्बतियों को मार डाला है और 6000 तिब्बती मठों को नष्ट कर दिया है और अभी भी सांस्कृतिक संहार जारी है। आज, तिब्बत के भीतर तिब्बती डर और अपनी जान और अपनी पहचान खोने की चिंताओं के साथ जी रहे हैं।

निजी तौर पर मैंने 1999 में केवल आठ साल की उम्र में तिब्बत छोड़ दिया और मेरे निर्वासन की यात्रा में कई महीनों तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। दिन के समय, हमें सोना पड़ता था ताकि हम रात में चल सकें जिससे हमें सीमाओं पर चीनी सैनिकों के ध्यान से बचने में मदद मिली। बर्फ पर व्यापक रूप से चलने के कारण कई तिब्बतियों को शीतदंश और हिम-अंधापन का सामना करना पड़ा और कई अन्य लोगों की लंबी यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। यह दर्दनाक स्थिति 2006 में भी जारी है, जब चीनी सैनिकों ने एक तिब्बती भिक्षुणी को गोली मार दी थी। उस समय वह भिक्षुणी हिमालय पार करने का प्रयास कर रही थी। यह केवल उस कठिनाई की एक झलक है जिसका सामना कई तिब्बतियों ने विदेशी कब्जे के तहत अपनी मातृभूमि तिब्बत से भागते समय किया है।

इन उथल-पुथल भरे वर्षों के बाद भी परम पावन के नेतृत्व में भारत में निर्वासित तिब्बती अक्षुण्ण बने हुए हैं और दुनिया में तिब्बतियों के लिए एक मजबूत आवाज बन गए हैं। लेकिन तिब्बत में अब तक 155 तिब्बतियों ने सीसीपी की कठोर नीतियों और अत्याचारों के विरोध में आत्मदाह कर लिया है। पिछले साल तीन बच्चों की मां ल्हामो नाम की एक तिब्बती महिला ने चीनी जेल में क्रूर यातना के कारण दम तोड़ दिया। तिब्बत में हजारों तिब्बती हैं जिन्होंने इसी तरह के दुर्भाग्य का सामना किया है, फिर भी उनकी स्थिति और ठिकाने अज्ञात हैं और क्रूर शासन द्वारा दबा दिए गए हैं। स्थिति की गंभीरता के बावजूद चीनी विदेश प्रवक्ता हुआ चुनयिंग गर्व से ट्वीट करती हैं, 'चीन एक ऐसा देश है जो हमेशा लोगों के लोकतंत्र को बनाए रखता है और बढ़ावा देता है।' अपनी मातृभाषा सीखने, खुले तौर पर अपने धर्म और रीति-रिवाजों का पालन करने और परम पावन की अपनी मातृभूमि में वापसी का गवाह बनने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए आत्मदाह करके अपनी जान गंवाने वाले 155 तिब्बतियों ने इस तरह के झूठ का पर्दाफाश किया है।

आज, सीसीपी तिब्बत में 'श्रम स्थानांतरण नीति' लागू कर रही है। चीन के विशेषज्ञ और मानविज्ञानी, एड्रियन ज़ेंज़ लिखते हैं कि इस कानून के तहत, तिब्बती खानाबदोशों और किसानों को उनकी 'पिछड़ी सोच' में सुधार के उद्देश्य से केंद्रीकृत 'सैन्य-शैली' में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। इस तरह के माध्यम से तिब्बतियों को जबरदस्ती किसी कार्य में लगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर, इस तरह की जबरदस्ती साबित करती है कि सीसीपी तिब्बत

पर 70 साल के कब्जे के बाद भी तिब्बतियों की निष्ठा नहीं जीत सकी है। मानवाधिकारों के उल्लंघन का सीसीपी का कुख्यात इतिहास 4 जून 1989 को सीसीपी के नेताओं ने बीजिंग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते ह - अधिक लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों लोकतंत्र समर्थक कॉलेज के छात्रों की हत्या का आदेश दिया। यह घटना सीसीपी की मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूची में एक अमिट जोड बन गई। तियानमेन चौक नरसंहार के एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्दों में. आज तियानमेन चौक चौबीसों घंटे निगरानी में एक आकर्षण पर्यटन केंद्र बन गया है। उदाहरण के लिए, वहां पर कैमरों के समूह लैंप पोस्ट के रूप में चारो ओर छिपाकर लगाए गए हैं, और चौक के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा दिया गया है जो 1989 की घटनाओं की याद दिला सकता था। पिछले साल चीनी-अमेरिकी अरबपति एरिक युआन द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन वीडियो चैटिंग सेवा-ज़ुम- ने तियानमेन स्क्वायर त्रासदी को मनाने के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए अमेरिका में बस गए कुछ चीनी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाते को निलंबित कर दिया था। 04 जून को, 32वें तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का स्मरणोत्सव हांगकांग में आयोजित किया जाना है, लेकिन हांगकांग सुरक्षा ब्यूरो ने एक कठोर चेतावनी जारी की है कि तियानमेन स्क्वायर की निषिद्ध क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हांगकांग के लोगों को पांच साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड सकता है और अगर कोई इस कार्य को बढ़ावा देने की हिम्मत भी करता है तो उसे एक साल की सजा दी जाएगी। मूल चीन और भी खराब होगी यदि लोकतंत्र समर्थक क्रूसेडर्स तियानमेन स्क्वायर स्मरणोत्सव का आयोजन करते हैं। हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वे बाद में कहां पहुंचेंगे। दुनिया भर के राष्ट्र सार्वजनिक रूप से तिब्बत, ताइवान और तियानमेन जैसे 3टी पर चर्चा करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे एशियाई ड़ैगन के क्रोध का शिकार बन जाएं। चीन को हत्यारा के तौर पर पहचान करानेवाले और उसके जनवादी अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाने वाले सदी के सबसे कटू सत्य को दबाने की बारी आने पर सीसीपी का चेहरा ऐसा ही बन जाता है।

पूर्वी तुर्केस्तान (झिंझियांग) और हांगकांग पर सीसीपी की पकड़ पूर्वी तुर्केस्तान में सीसीपी का व्यापक श्रम प्रशिक्षण (पढ़ें: नरसंहार) दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए, लीक हो गए एक चीनी सरकारी दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि झिंझियांग में 2018 के वसंत तक हिरासत शिविरों में 68 झिंजियांग काउंटियों में 8,92,000 लोगों को रखा गया था। एड्रियन ज़ेनज़ का अनुमान है कि झिंजियांग में पुन: शिक्षा इंटर्नमेंट का कुल आंकड़ा केवल दस लाख तक हो सकता है। कुछ महीने पहले, चीनी लोग एक स्वीडिश फैशन रिटेलर- एच एंड एम- का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे थे, जिसने एक टिप्पणी की थी कि 'वह झिंझियांग में जबरन श्रम के आरोपों की रिपोर्टों के बारे में गहराई से चिंतित है और यह चीन के इस क्षेत्र से उत्पादों का संग्रह नहीं करेगा।' यह साबित करता है कि झिंझियांग में जो कुछ भी हो रहा है वह बाकी दुनिया के लिए एक रहस्य है।

उसी कठोर दृष्टिकोण के साथ, सीसीपी ने हांगकांग में 'अम्ब्रेला मूवमेंट' पर परोक्ष रूप से नकेल कस दी। जोशुआ वोंग जैसे कई लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को हाल ही में हिरासत में लिया गया था। ये अत्याचार उसी प्लेबुक से निकले हैं, जिसका इस्तेमाल सीसीपी ने तिब्बत में किया था। 'हांगकांग का वर्तमान तिब्बत का अतीत हैं'। यह बाकी दुनिया के लिए एक सौम्य यादगार है कि 1950 के दशक में तिब्बत द्वारा मदद की अपील के बाद कैसे सब कुछ बदल गया और चीन ने पहले उंगली पकड़कर कैसे पूरे तिब्बत को निगल लिया।

सीसीपी की पकड़ बढ़ रही है

शी जिनपिंग द्वारा माओ की 'पांच-उंगली की रणनीति' पर जोर देने के साथ सीसीपी का विस्तारवादी डिजाइन पूरे हिमालय में स्पष्ट है। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक सीसीपी अपना क्षेत्रीय वर्चस्व साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बेल्ट एंड रोड पहल के वेष में इसके प्रभाव का इस्तेमाल सीसीपी दुनिया भर के कई देशों में उपनिवेश स्थापित करने में कर रही है। अब समय आ गया है कि हम महसूस करें कि तिब्बत के साथ जो हुआ वह कोई अपवाद नहीं था, यह एक नमूना था। राष्ट्रपति डॉ. लोबसांग सांगेय ने एक बार कहा था कि या तो हम चीन को बदल दें या चीन हमें बदल देगा। इस संदेश को साकार करने के लिए, तिब्बत की कथा सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सीसीपी ने तिब्बत को जीतने के लिए जिस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया, उसे कई अन्य सीमाओं पर लागू किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, सीसीपी की 100वीं वर्षगांठ रक्तरंजित इतिहास, आंसुओं के सैलाब और अत्याचारों की परिणति के अलावा और कुछ नहीं है।

*येशी दावा वर्तमान में तिब्बत नीति संस्थान में संबद्घ फेलो और तिब्बत टीवी में एंकर हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार जरूरी नहीं कि तिब्बत नीति संस्थान के विचारों को प्रतिबिंबित करें। यह लेख मूल रूप से 04 जून 2021 को ग्लोबल ऑर्डर में प्रकाशित हुआ था।

• इतिहास गवाह है कि हिमालय में एशिया को नियंत्रित करने की कुंजी है; भारत को चीन से सावधान रहना चाहिए

tibetpolicy.net, 21 जून 2021

भविष्य में तिब्बत के अंदर जो कुछ भी होता है वह भारतीय सुरक्षा वातावरण के लिए और एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अपने उच्च तकनीक वाले हथियारों को उन्नत किया है और हिमालय की सीमाओं और तिब्बत में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास की एक



शृंखला आयोजित की है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल टाइम्स ने 5 जनवरी, 2020 को रिपोर्ट किया कि चीन के नवीनतम हथियार जिनमें टाइप 15 टैंक और नए 155-मिलीमीटर वाहन- चालित होवित्जर शामिल हैं, दक्षिण-पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। यहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अपने इस अभ्यास शृंखला की पहली कड़ी 2020 में शुरू की थी।

शी जिनिपंग के सत्ता में आने के बाद, 2015 में पीएलए में एक बड़ा पुनर्गठन किया गया और बाद में -/फरवरी 2016 में सात सैन्य क्षेत्रों को पांच थिएटर कमान में पुनर्गठित किया गया। 01 फरवरी, 2016 को बीजिंग में आयोजित आधिकारिक ध्वज-सम्मेलन समारोह के दौरान केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के अध्यक्ष का भी पदभार संभाल रहे शी ने थिएटर कमांडों को कमांड करने की अपनी क्षमता में सुधार लाने और नियमित संघर्ष में तत्परता लाने और सैन्य

कार्रवाइयों में संयुक्त कमान को मजबूती प्रदान कर कार्यों को पूरा करने का आग्रह किया।

तब से, विभिन्न सघन सैन्य अभ्यास हुए हैं, जिसमें पश्चिमी थिएटर कमान सहित विभिन्न थिएटर कमानों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शामिल है, जो पूर्वी तुर्केस्तान (झिंझियांग) और तिब्बत की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। कमांड सिस्टम का यह केंद्रीकरण इस बात का संकेत देता है कि चीन भारत-तिब्बत सीमा पर एक नया मोर्चा बनाने की योजना बना रहा है।

दूसरे शब्दों में, तिब्बत में चीन के सैन्य अभ्यासों की बढ़ती संख्या से भारत के सामने खतरा बढ़ गया है।

पिछले साल जून में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य और राजनियक गितरोध के दौरान, भारत के साथ बातचीत करने के बावजूद, उपग्रह छिवयों ने साबित कर दिया कि पीएलए अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को सिक्रय रूप से उन्नत कर रहा है। गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो में सड़कों के निर्माण को रोकने के लिए भारत पर दबाव डालते हुए, चीन भारत की सीमा से लगे तिब्बत में एक उन्नत परिवहन नेटवर्क और सैन्य बुनियादी ढाँचा विकसित करना जारी रखे हुए है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सार द्वारा जारी उपग्रह चित्रों से यह और साबित हो जाता है। पीएलए द्वारा निर्मित सैन्य हार्डवेयर के लिए बंकर, टेंट और भंडारण इकाइयों से युक्त संरचनाएं जून से पहले हवाई तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही थीं। इसलिए, भारत के साथ व्यवहार में कम्युनिस्ट चीन की ओर से दोहरा बर्ताव किया जा रहा है।

'हिमालयन फेस-ऑफ़: चाइनीज़ एसेरशन एंड द इंडियन रिपोस्टे' के 37 वर्षीय लेखक शिशिर गुप्ता की एक रिपोर्ट 20 नवंबर, 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि "सैन्य कमांडरों और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पिछले एक महीने में उन्होंने देखा कि पीएलए केंद्रीय क्षेत्र में कौरिक दर्रे के पार चुरुप गांव में सड़क निर्माण में संलग्न है और उन्होंने उत्तराखंड में बाराहोती मैदानों के उत्तर में टुनजुम ला के आसपास नए कंटेनर हाउसिंग मॉड्यूल रखे हैं, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 565 किमी एलएसी से सिर्फ चार किलोमीटर दूर है।

ज्ञातव्य है कि कौरिक दर्रे के ठीक सामने एक सड़क के निर्माण से भारत की सुरक्षा को खतरा है। इतना ही नहीं, पूर्वी तुर्केस्तान-तिब्बत राजमार्ग का अस्तित्व, जो कौरिक दर्रे के करीब है, भारत के साथ 1962 के सीमा युद्ध के समय पीएलए के सैनिकों और सैन्य हार्डवेयर की तैनाती के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़कों में से एक रहा है।

29 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के साथ किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में लेपचा के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया।

निरीक्षण के बाद आउटलुक पत्रिका ने कैबिनेट मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा के साथ मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया था, 'यह सच है कि चीन तिब्बत क्षेत्र में राज्य की सीमाओं के साथ सड़कों का निर्माण और अन्य ढांचागत परियोजनाओं को तैयार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन अपने निगरानी नेटवर्क को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित करने की योजना बना रहा है जो अधिक ऊंचाई पर स्थित हो, ताकि सीमाओं पर हमारी ओर नजर रखी जा सके।'

समाचार

तिब्बती पठार पर चीनी अवसंरचना का यह निरंतर विकास तिब्बत के महत्व की पृष्टि करता है।

सामरिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिलों में तिब्बत के साथ 260 किलोमीटर लंबी झरझरा सीमा लगती है। कुल सीमा की लंबाई में से 140 किलोमीटर किन्नौर जिले में हैं, जबिक 80 किलोमीटर लाहौल और स्पीति जिलों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, तिब्बत में राडार स्टेशन पर 5जी की स्थापना से सैन्य संचार में और वृद्धि होगी और भारत-तिब्बत सीमा पर सेना और हथियारों की तेजी से तैनाती के लिए एक विशाल नेटवर्क स्थापित हो जाने की आशंका है।

पिछले एक दशक से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के नाम पर, लगभग 2,66,000 तिब्बती खानाबदोश और किसानों को भारत- तिब्बत सीमा के पास 960 नए पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। इन सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रमों की दीर्घकालिक योजना तिब्बत सीमा को आबाद करना और उसकी रक्षा करना है। इसके अलावा तिब्बत में पार्टी-राज्य ने प्रमुख पृथक सीमावर्ती गांवों को राजमार्गों से व्यवस्थित रूप से जोड़ा है और अधिकांश सीमावर्ती गांवों को अब केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क के तहत लाया गया है।

2017 में कम्युनिस्ट चीन ने 'सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम समृद्धि के गांवों के निर्माण (2017-2020)' के लिए अपनी योजना जारी की। इस योजना का उद्देश्य तिब्बत के लिए शी की शासन रणनीति द्वारा निर्देशित है: देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए हमें पहले सीमाओं पर अच्छी तरह से शासन करना चाहिए, और

सीमाओं पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए हमें पहले तिब्बत की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए।'

भारत-तिब्बत सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 11 दौर की बातचीत के बावजूद चीन ने हिमालय को लेकर अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ी है।

सैन्य तैयारियों और रणनीतिक गणना से ऐसा लगता है कि चीन का शुरुआती रणनीतिक कदम तिब्बत-हिमाचल सीमा की ओर स्थानांतरित होना है।

लगभग छह दशक पहले, जॉर्ज गिन्सबर्ग्स और माइकल मैथोस ने तिब्बत के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त किया: 'वह जो तिब्बत को धारण करता है वह हिमालय पीडमोंट पर हावी है; वह जो हिमालय पीडमोंट पर हावी है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खतरा है; और जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खतरा है, अंतर जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खतरा है, उसके नियंत्रण में संपूर्ण दक्षिण एशिया और इस तरह संपूर्ण एशिया हो सकता है।'

संक्षेप में, भविष्य में तिब्बत के भीतर जो कुछ भी होता है वह भारतीय सुरक्षा परिवेश के लिए और एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

डॉ. त्सेवांग दोरजी धर्मशाला में तिब्बत नीति संस्थान में रिसर्च फेलो हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार जरूरी नहीं कि तिब्बत नीति संस्थान के विचारों को प्रतिबिंबित करें। इस लेख को 21 जून 2021 को TheFirstPost.com में पुनप्रकाशित किया गया था।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.

Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.

You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.

We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Jigmey Tsultrim Coordinator India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।

तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।

आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।

इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई—मेल पर भेज सकते है।

अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

जिगमे त्सुलट्रिम समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच-10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर-03, नई दिल्ली-110024

फोनः 011—29830578, 29840968 ई—मेलः indiatibet7@gmail.com



वेबिनार मे जुड़े कनाडा के सांसद।



कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज़ के सदस्य के साथ वार्तालाब करते तिब्बत के सिक्यांग पेंपा छेरिंग।